सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 01, अंक 297, नई दिल्ली । शनिवार, 06 जनवरी 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने छोटे-छोटे कामों में भी अपने दिल ,दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए, यही सफलता का रहस्य है ।

03 संजय सिंह को राज्यसभा भेजने पर भड़की भाजपा

06 पाकिस्तान में बलूचों का सत्याग्रह

08 इस साल रिटायर होंगे 68 राज्यसभा सांसद...

सड़क मंत्रालय ने 2047 तक 50,000 किमी.

हाई-स्पीड कॉरिडोर बनाने का रखा प्रस्ताव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2047 तक 50,000 किलोमीटर तक लंबे हाई-स्पीड (एक्सेस-नियंत्रित) कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2047 तक 50,000 किलोमीटर तक लंबे हाई-स्पीड (एक्सेस-नियंत्रित) कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

संजय बाटला

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2047 तक 50,000 किलोमीटर तक लंबे हाई-स्पीड (एक्सेस-नियंत्रित) कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग (एनएचएआई) सचिव अनुराग जैन ने कहा, पूरी हो जाने पर, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर ट्रकों की औसत यात्रा की रफ्तार मौजूदा 45 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 75-80 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी।

उनकी जानकारी के अनुसार, जहां 2014 में हाई-स्पीड कॉरिडोर की कुल लंबाई 353 किलोमीटर थी, जो 2023 में बढ़कर 3,913 किलोमीटर हो गई।

उन्होंने कहा, हमने बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप दिया है ... उस दस्तावेज में, हमने 2047 तक हाई स्पीड वाले गलियारों की कुल लंबाई को 50,000 किलोमीटर तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।

एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के 2047 तक लगभग 30 ट्रिलियन (300 खरब) अमरीकी डॉलर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीति आयोग एक विजन दस्तावेज तैयार कर रहा है, जिसे प्रधानमंत्री जनवरी के आखिर तक जारी करेंगे।

2023 में, आयोग को दस क्षेत्रीय विषयगत दृष्टिकोणों को ₹विकसित भारत @2047₹ के संयुक्त दृष्टिकोण में समेकित करने का कार्य सौंपा गया था।

उन्होंने कहा कि परियोजनाओं का आवंटन विजन 2047 के अनुरूप होगा ताकि क्रियान्वयन में सुधार हो और ओवरलैप कम हो।

जैन के मुताबिर, 108 (3,700 किलोमीटर) बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़क परियोजनाओं में से 8 (294 किलोमीटर) पूरी हो चुकी हैं, 28 (1,808 किलोमीटर) को अनुमोदित किया गया है और 72 (1,595 किलोमीटर) परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रगति पर हैं।

उन्होंने कहा कि परवतमाला परियोजना के तहत, इस वित्तीय वर्ष के आखिर तक 60 किलोमीटर की रोपवे परियोजनाओं को अनुमोदन के लिए रखा गया है।

जैन ने बताया कि वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में 3.85 किलोमीटर का रोपवे निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा कि 36 किलोमीटर लंबाई की नौ परियोजनाओं के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

जैन ने कहा कि 2018 में टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) मॉडल के लॉन्च के बाद से, एनएचएआई ने टीओटी मोड के जरिए सड़क संपत्ति के मोनेटाइजेशन के छह राउंड पूरे किए हैं और 26,366 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

सड़क पर सुरक्षा के कानून का नाहक विरोध....

भारत सरकार ने बीते संसद सत्र में जिस नयी न्याय संहिता का निर्माण किया है उसमें एक्सीडोन्ट के मामले में दोषियों की सजा बढ़ाई है और जुर्माना भी। 'हिट एण्ड रन' मामलों में जहां वाहन चालक एक्सीडेन्ट करके भाग जाता है, वहां अब 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

संजय तिवारी

सड़क पर सुरक्षा के कानून का नाहक विरोध सड़क पर चलते समय भारत में एक अघोषित नियम काम करता है। वह यह कि अगर दो गाड़ियों में एक्सीडेन्ट हो जाए तो गलती हमेशा बड़ी गाड़ी वाले की मानी जाती है। मसलन, किसी फोर व्हीलर से किसी बाइक की टक्कर हो जाए तो दोष हमेशा फोर व्हीलर वाले के ऊपर डाला जाएगा।

इसी तरह किसी ट्रक या बस वाले की टक्कर किसी फोर व्हीलर वाले से हो जाए तो ट्रक या बस का ड्राइवर ही दोषी मान लिया जाता है।

चूक किसने की, गलती किसकी थी इसकी विवेचना भी अक्सर छोटी गाड़ियों वाले के पक्ष में ही जाती है। अगर उसमें छोटी गाड़ी चलानेवाले की जान चली गयी, फिर तो बड़ी गाड़ी वाला पक्का दोषी सिद्ध होता है। हालांकि भारत में अब तक ऐसे 'दोषियों' के लिए अधिकतम सजा 2 साल की ही होती थी, इसलिए 'दोषी' को आर्थिक दंड भले चाहे जो लग जाए जेल जाने की संभावना कम ही रहती है। भारत की पुरानी कानून व्यवस्था में दो साल तक की सजा मिलने पर आसानी से जमानत मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा।

भारत सरकार ने बीते संसद सत्र में जिस नयी न्याय संहिता का निर्माण किया है उसमें एक्सीडोन्ट के मामले में दोषियों की सजा बढ़ाई है और जुर्माना भी। रहिट एण्ड रनर मामलों में जहां वाहन चालक एक्सीडेन्ट करके भाग जाता है, वहां अब 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ऐसा प्रावधान करने से पहले दुनियाभर के कानूनों का अध्ययन किया गया और पाया गया कि जहां एक्सीडेन्ट से जुड़े कठोर कानून हैं वहां एक्सीडेन्ट कम हो रहे हैं। वाहन चालक अधिक सावधानी से गाड़ी चला रहे हैं और सड़क के नियमों का पालन कर रहे हैं।

लेकिन यूरोप या अमेरिका आदि की तुलना में भारत में जो एक बड़ा विरोधाभास है वह है यहां दोपहिया वाहनों की संख्या। भारत में कुल 32 से 33 करोड़ के बीच वाहन सड़कों पर हैं जिसमें से तीन चौथाई दोपहिया वाहन हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश ही नहीं है बल्कि सबसे अधिक दोपहिया वाहन वाला देश भी है। इसलिए सबसे अधिक सड़क दुर्घटना का शिकार भी दोपहिया वाहन ही होते हैं। इसके अलावा बड़े ट्रकों या बसों की चपेट में चार पहिया वाहन भी आते हैं।

दुनियाभर की सड़कों पर जितने एक्सीडेन्ट होते हैं उसमें अकेले 11 प्रतिशत भारत में होते हैं। 2022 में साढे चार लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं जिसमें 1 लाख 60 हजार से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इतने लोग सड़क हादसों में मारे जाएं तो निश्चित रूप से सरकारों को चौकन्ना होने की जरूरत होती है। सरकार के पास नियम कानून बनाने का अधिकार होता है और उसने नयी न्याय संहिता में हिट एण्ड रन के मामले में कठोर सजा का प्रावधान करके ड्राइवरों को सचेत रहकर गाड़ी चलाने का संदेश दे दिया है।

अब महाराष्ट्र सहित देश के अधिकांश हिस्से के ट्रक और बस ड्राइवर इस कानून के विरोध में चक्का जाम पर उतर आये हैं। उनकी शिकायत है कि यह ड्राइवरों के साथ अन्याय है। उनका तर्क है कि सड़क पर एक्सीडेन्ट की स्थिति में अगर वह गाड़ी छोड़कर न भागें तो वहां इकट्ठा होनेवाले लोग ही ड्राइवरों की पीटकर हत्या कर देंगे। उनकी यह शिकायत अनुचित नहीं है। एक्सीडेन्ट की अवस्था में सामाजिक नियमों के मुताबिक दोष तो बड़ी गाड़ी वाले का ही माना जाता है और अदालत में

भी यही बात सही मानी जाती है।

लेकिन यहां एक बात समझनेवाली है कि नयी न्याय संहिता के सेक्सन 104(2) में यह प्रावधान किया गया है कि अगर एक्सीडेन्ट की अवस्था में 'दोषी' चालक पुलिस को सूचित नहीं करता है तो ही उसे हिट एण्ड रन के तहत दोषी माना जाएगा। अगर वह पुलिस स्टेशन या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दे देता है कि उसकी गाड़ी से एक्सीडेन्ट हो गया है तो उसके लिए सात साल की सजा का प्रावधान नहीं होगा।

भारत में यह देखने में आया है कि अगर लोगों की नजर न पड़े तो एक्सीडेन्ट करनेवाले ड्राइवर कई बार गाड़ी सहित तो कई बार गाड़ी छोड़कर फरार हो जाते हैं। ऐसे में जो हादसे का शिकार होते हैं उनके या उनके परिवार को न्याय नहीं मिल पाता है। सरकार ने जो नया प्रावधान किया है वह बहुत सूझबूझकर किया है। अगर 'दोषी' ड्राइवर पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित कर देता है तो उसे 10 साल की कठोर सजा से डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उसका पक्ष भी सुना जाएगा और जज के विवेक पर निर्भर करेगा कि वह उसे कितनी सजा या जुर्माना सुनाता है। 10 साल की सजा भी वहां दी जाएगी जहां एक्सीडेन्ट में सामनेवाले की मौत हो जाएगी।

देश में हिट एण्ड रन के एक से एक कुख्यात मामले सामने आ चुके हैं। सवाल सिर्फ गरीब ट्रक चालकों का नहीं है। अमीर बाप की बिगड़ी औलादों के कई केस देश में चर्चित हो चुके हैं। 2002 का सलमान खान का चर्चित हिट एण्ड रन केस ही नहीं, मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में आये दिन ऐसे केस होते रहते हैं जिसमें कोई न कोई कारवाला किसी को कुचलकर चला जाता है और उसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं होती। मुंबई में पुलिस अधिकारियों का यह भी कहना है कि फिल्मों की तर्ज पर अब एक्सीडेन्ट करके हत्या करना भी अपराध का एक तरीका बनता जा रहा है।

ऐसे में सख्त कानून ही हैं जो लोगों के साथ न्याय कर सकते हैं। आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की ओर से चक्का जाम करवाकर इस तरह देशभर की सप्लाई लाइन को बाधित करना कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता। ट्रक बस ड्राइवरों की जो आशंकाएं हैं उसे सरकार के स्तर पर बताया जा सकता है और बीच का कोई रास्ता निकाला जा सकता है कि बड़ी गाड़ी वालों को ही एकतरफा दोषी न मान लिया जाए। लेकिन न्याय संहिता में जो नये प्रावधान किये गये हैं उनका स्वागत करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से देश की सड़कों पर लापरवाही से वाहन चलानेवालों को सबक मिलेगा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयेगी।

वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन ने 2021-2030 को सड़क सुरक्षा कार्रवाई दशक घोषित किया है। उसका लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक दुनिया भर में सड़क हादसों की संख्या आधी कर दी जाए।

इसको लेकर डब्ल्यूएचओ द्वारा सौ से अधिक देशों में 2010 से 2021 तक सड़क परिवहन की स्थिति का अध्ययन किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अध्ययन अवधि के दौरान वैश्विक स्तर पर सड़क हादसों की संख्या में 5% की गिरावट आई है, लेकिन इसी अवधि के दौरान भारत में दुर्घटनाओं की संख्या में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है।

इन बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है तो कठोर कानून बनाने ही पड़ेंगे। साथ ही सड़क पर चलनेवालों को नियम कानूनों का पालन करना होगा। सड़क पर होने वाले हादसों में जान किसी की भी जाए, मरता सिर्फ वही नहीं बल्कि कोई न कोई घर टूटता है। कोई न कोई बच्चा अनाथ होता है और कोई न कोई स्त्री विधवा होती है। इसलिए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कानून समय की मांग है। नयी न्याय संहिता के प्रावधान का विरोध नहीं बल्कि स्वागत करने की जरूरत है।

बस मार्शलों का सीएम हाऊस पर रोजी रोटी प्रदर्शन

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। नई दिल्ली। पिछले 70 दिनों से अपने रोजी-रोजगार को वापिस लेने के संघर्ष में दिल्ली सचिवालय के बाहर सडक पर गर्मी-सर्दी को झेलते हुए धरना-प्रदर्शन कर रहे हजारों बस मार्शलों की जब सुध लेने कोई नहीं आया तो उनका सब्र जवाब दे गया। शुक्रवार को हजारों की संख्या में महिला-पुरूष बस मार्शलों ने बा-वर्दी सीएम केजरीवाल के आवास का घेराव किया।

शुक्रवार को हजारों की संख्या में तमाम बस मार्शल सुबह से चंदगी राम अखाडा, सिविल लाइन्स ट्रामा सेंटर के बाहर रिंग रोड पर एकत्र हुए। इक्कठे हुए बस मार्शलों ने मुख्यमंत्री आवास के लिए हाथों में तिरंगे झंडे थामें जोशीले नारे केजरीवाल होश में आओ, हमारा छीना रोजगार वापिस दो, रोजगार नहीं तो वोट नहीं जैसे नारे लगाते हुए सीएम आवास की तरफ बड गये। पुलिस बैरिकेट को तौलते हुए गुस्साए मार्शलों ने सभा की और जमकर दिल्ली सरकार के जिम्मेदार, नेता,मंत्रियो, अधिकारियों के खिलाफ अपनी भड़स निकाली। मार्शलों का दर्द था कि अपनी नौकरी बहाली को लेकर 11 मार्शलों की मौत हो गई। लेकिन 55 करोड के घर और 55 लाख की गाडी में चलने वाले कथित आम आदमी, कट्टर इमानदार सीएम केजरीवाल और उनके मंत्रियों ,विधायक ने आज तक हमारी ,हमारे बच्चों तक की सुध नही ली। चेतावनी देते हुए मार्शलों ने कहा कि अगर हम इतनी ठंड में सडक पर हैं, तो हम वोटों के बल पर उन्हें भी सडक पर ले आएगे। हमारी सीधा सी मांग है कि इस बढती उम्र में अब अब कहां जाए? हमें हमारा रोजगार वापिस दिया जाए। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व आदित्य रॉय, मुकेश, सचिन समेत ,महिला मार्शल नेताओ ने भी किया। सभी मार्शल नेतृत्वकारी ने चेतावनी में कहा कि आज हजारों संगठित मार्शलों के रोजगार की मांग पर कोई कारवाई नहीं की गई, तो धरना-प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगा। हम फिर से इससे भी बडे प्रदर्शन का आयोजन करेंगे।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

आज का परिचयः- स्त्री - पुरुष का रिश्ता

आज के दौर में स्त्री सशक्त हो रही है, उसे अब पुरुष के सहारे की आवश्यकता नहीं है, इससे स्थिति बदल नहीं जाती। सशक्त स्त्री अपने से अधिक सशक्त पुरुष चुनेगी। ऐसा नहीं कि सशक्त स्त्री कोई सा भी पुरुष चुन लेगी। लड़की डीएम बन जाती है तो अपने कलीग को चुनती है, चपरासी को नहीं। डॉक्टर होती है तो अपने से अधिक सफल डॉक्टर को चुनती है, वार्ड बॉय को नहीं।

स्त्री ऐसा पार्टनर खोजती है जो उससे सुपीरियर हो, जो परिवार में प्रभुत्व की स्थिति में रह सके, जो उसे डोमिनेट करना डिजर्व करता हो। यदि पुरुष ऐसा नहीं होगा तो परिवार में समस्याएं होंगी। स्त्री उसका सम्मान नहीं कर सकेगी। सम्मान का अर्थ यहां सुबह उठकर पैर छूना, पैर धोकर पीना नहीं है... म्यूचुअल रिस्पेक्ट का वह मिनिमम लेवल जो परिवार के फंक्शन की शर्त है, वह टूट जायेगा। ऐसा पुरुष कुंठा में रहेगा, और अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए हिंसक और उग्र हो जायेगा। डोमेस्टिक एब्यूज उन परिवारों के सिम्पटम्स हैं जहां यह समीकरण सहज स्थापित नहीं होता। या तो पुरुष इस योग्य नहीं होता, या फिर स्त्री अपने डिल्यूशन में में इस स्थिति को प्राकृतिक स्थिति स्वीकार करने से इंकार कर देती है। और यदि पुरुष इस स्थिति को, परिवार में निचले पायदान पर होने को, विनम्रता से स्वीकार कर लेगा तो यह और बुरी स्थिति होगी.. ऐसा पुरुष स्त्री को ही स्वीकार्य नहीं होगा। वह खुद इस अप्राकृतिक स्थिति का बोझ उठाने में थक जायेगी।

महिलाएं... फेमिनिस्ट्स और ऐसी फेमिनिस्ट जिन्हें मालूम नहीं हैं कि वे फेमिनिस्ट हैं, यह प्रश्न कर सकती हैं कि क्या अपनी पुत्री को भी यही सलाह दूंगा कि वह परिवार में पुरुष का प्रभुत्व स्वीकार करे.. मेरा उत्तर है, मैं उसे ऐसा पुरुष चुनने की सलाह दूंगा जो इस योग्य हो कि वह उसका प्रभुत्व स्वीकार कर सके। मैं कहूंगा, आत्मनिर्भर बनो, सशक्त बनो... पर पुरुष ऐसा चुनो जो तुमसे अधिक सशक्त हो, जिसपर तुम निर्भर कर सको। ड्राइविंग सीखो जरूर, लेकिन जीवन पैसेंजर सीट पर शांति से बिता सको ऐसा पार्टनर चुनो।

क्योंकि रियलिटी ऑप्शनल नहीं होती। आज की स्त्री ऐसा सोचती है और वैसा सोचती है... यह रिटोरिक रियलिटी को जरा भी प्रभावित नहीं करता। आप अपनी मर्जी की रियलिटी इमेजिन कर सकते हैं...और फिर उसका परिणाम भुगत सकते हैं। ऐज ए पैरेंट मेरा काम सिर्फ अपनी बच्ची को गुड़िया रानी, एंजल और राजकुमारी बनाना नहीं है, उसको रियलिटी समझाना है। उसको गाइड करना है, पैंडर नहीं करना। प्रकृति प्रदत्त मनोविज्ञान के अनुसार आप क्या चाहते हैं, और आप जो सोचते हैं कि

> **महिलाएं... फेमिनिस्ट्स और ऐसी फेमिनिस्ट जिन्हें मालूम नहीं हैं कि वे फेमिनिस्ट हैं, यह प्रश्न कर सकती हैं कि क्या अपनी पुत्री को भी यही सलाह दूंगा कि वह परिवार में पुरुष का प्रभुत्व स्वीकार करे.. मेरा उत्तर है, मैं उसे ऐसा पुरुष चुनने की सलाह दूंगा जो इस योग्य हो कि वह उसका प्रभुत्व स्वीकार कर सके। मैं कहूंगा, आत्मनिर्भर बनो, सशक्त बनो... पर पुरुष ऐसा चुनो जो तुमसे अधिक सशक्त हो, जिसपर तुम निर्भर कर सको।**

आप क्या चाहते हैं... के बीच एक संकरी पर गहरी खाई है और मेरा काम मुझे उस खाई से बचाना है ... ना कि बाद में उस खाई से उसके जीवन के टुकड़े चुनना।

ऐसे परिवार शायद ही कोई मिलते हों जिसमें स्त्री पुरुष से बहुत श्रेष्ठ हो (कैरियर में, शिक्षा में, व्यक्तित्व में) और सब कुछ ठीक ठाक चलता हो। ऐसी जोड़ियां पहले तो बनती नहीं, अगर बनती हैं तो ऐसे परिवार अस्थिर होते हैं, अक्सर टूट कर बिखर जाते हैं इसके बहुत से उदाहरण उपलब्ध है आईएएस अधिकारियों के)। यदि विवाह के बाद स्त्री अप्रत्याशित प्रगति कर ले तो उसका पति को डम्प कर देना कोई आकस्मिक घटना नहीं होती।

मैं किसी की आलोचना नही कर रहा हूं ना कोई जजमेंट दे रहा हूं। बस, सामान्य मनःस्थिति का वर्णन कर रहा हूं। प्रकृति में पार्टनर चुनना महिलाओं का प्रिविलेज है और वह यह प्रिविलेज प्रयोग करती हैं।

सूर्य ग्रह व हृदय रोग

वैदिक ज्योतिष में नवग्रहों का वर्णन मिलता है। अगर ये ग्रह व्यक्ति की जन्मकुंडली अशुभ या नीच स्थित हों तो व्यक्ति को उन ग्रह से संबंधित रोग व्यक्ति को हो सकते हैं।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ₹सूर्य ग्रह₹ हृदय रोग का प्रमुख कारण ग्रह होता है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह अशुभ अवस्था में है तो हृदय रोग का सामना करना पड़ सकता है। कभी-कभी चंद्रमा की अशुभ अवस्था भी हृदय रोग का कारण बन जाती है।

आईये जानते जन्म कुंडली में कौन सी स्थितियां हृदय रोग को जन्म देती है और उसके उपाय-:

ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह यदि चतुर्थ भाव में हो और पाप ग्रहों से पीडित हों तो हृदयरोग हो सकता है।

जन्मकुंडली में सूर्य ग्रह यदि शत्रु राशि या कुंभ राशि में हो तो धमनी में अवरोध उत्पन्न करते हैं। जिससे व्यक्ति को हार्टरोग हो सकता है।

कुंडली में यदि चतुर्थ भाव में सूर्य-शनि की युति हो या मंगल, गुरु, शनि चतुर्थ भाव में हों या चतुर्थ या पंचम भाव में पापग्रह हों तो भी व्यक्ति को हृदय रोग से संबंधित परेशानी हो सकती है।

चतुर्थ भाव में पापग्रह हो और चतुर्थेश पापयुक्त हो तो हृदयरोग हो सकता है।

जन्मकुंडली के चतुर्थ भाव में राहु ग्रह, बुध व वक्री मंगल हों तो व्यक्ति को युवा अवस्था में ही हृदय रोग हो सकता है।

ज्योतिषीय उपाय-:

हृदय रोग की परेशानी से बचने के लिए, समय रहते हुए कुछ उपाय करके भविष्य में होने वाले हृदय रोग की संभावना में कुछ कमी की जा सकती है।

ज्योतिष के अनुसार प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का जाप हृदय रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। गायत्री मंत्र को आरोग्य का मंत्र माना गया है।

जिनका जन्म कुंडली में सूर्य खराब है, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए

सूर्य देव की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए रविवार का व्रत रखना चाहिए, (ध्यान रहे- रविवार के व्रत में नमक ना खाएं)

हृदय रोग के बचाव के लिए प्राणायाम करना बड़ा लाभकारी होता हैं जैसे-: अलोम- विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी जैसे प्राणायाम काफी लाभकारी होते हैं।

वैद्य की परामर्श से दालचीनी व अर्जुन की छाल का उपयोग करना चाहिए, ये हृदय रोग में बहुत लाभकारी होती है।

कौन होगा दिल्ली महिला आयोग का अगला अध्यक्ष? आप के इन नेताओं के नाम सबसे आगे

स्वाति मालीवाल के इस्तीफे के बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) का अगला अध्यक्ष कौन होगा। इस पद पर पार्टी नेतृत्व किसी ऐसे चेहरे को लाना चाहता है जो स्वाति मालिवाल की कमी की भरपाई कर सके। आम आदमी पार्टी में इस समय दो महिलाएं हैं जिनका इस पद के लिए नाम लिया जा रहा है।

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) का अगला अध्यक्ष कौन होगा, स्वाति मालिवाल द्वारा इस पद से इस्तीफा देने के बाद ये कयास शुरू हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि यह पद आम आदमी पार्टी के किसी नेता को ही मिलेगा। यह पद किसे मिले, यह तो आप नेतृत्व ही तय करेगा। मगर इस समय आप में दो नेताओं की ही इस पद पर अटकलें लगाई जा रही हैं।

स्वाति मालिवाल की कौन लेगा जगह

पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस पद पर पार्टी नेतृत्व किसी ऐसे चेहरे को लाना चाहता है जो स्वाति मालिवाल की कमी की भरपाई कर सके। पार्टी सूत्रों के अनुसार, स्वाति ने इस पद पर रहते हुए बहुत से लोगों को न्याय दिलाया है, पुलिस प्रशासन को भी इस पद की गरिमा का अहसास करा दिया है। स्वाति मालिवाल अक्सर रातों में भी औचक निरीक्षण पर निकलने को लेकर चर्चा में रही हैं।

कई बार उन्होंने महिलाओं से संबंधित किसी मुद्दे पर न्याय की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन, अनशन किया है।पार्टी नेतृत्व चाहता है कि इस पद पर इस तरह के नेता को लाया जाया जो इस पद के माध्यम से जरूरतमंदों को न्याय दिलाने के लिए मालिवाल की मुहिम को आगे बढ़ा सके। इस पद के लिए पार्टी में जो नाम सामने आ रहे हैं।

इन दो महिलाओं के नाम सबसे आगे

आम आदमी पार्टी में इस समय दो महिलाएं हैं, जिनका इस पद के लिए नाम लिया जा रहा है। इनमें प्रियंका कक्कड़ और रीना गुप्ता का नाम लिया जा रहा है। ये दोनों इस समय आप की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और कठिन समय में विरोधियों से लोहा लेने के लिए सबसे आगे खड़ी दिखती हैं। हालांकि, आम आदमी पार्टी में अन्य भी तेज तर्रार महिला नेता हैं, मगर जनप्रतिनिधि होने के कारण वे इस पद पर नहीं आ सकती हैं।

ऐसे में प्रियंका कक्कड़ और रीना गुप्ता का नाम ही इस पद के लिए लिया जा रहा है। प्रियंका काफी लंबे समय से पार्टी से जुड़ी हैं और उन्होंने एक आम कार्यकर्ता के रूप में काफी लंबा संघर्ष किया है। इन्होंने पहले तेलंगाना में पार्टी का संगठन खड़ा करने के लिए संघर्ष में अपना योगदान दिया है। वह साल 2017 से 2019 तक आप की तेलंगाना पर्यवेक्षक थीं, वह दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र की कानूनी प्रमुख भी थीं।

उन्होंने 2021 से 2023 तक राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। कक्कड़ ने उत्तर प्रदेश में पार्टी के कानूनी पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया, जहां वह राज्य संगठन के लिए गठित एक निगरानी समिति की सदस्य भी थीं। वहीं आप और आप सरकार में रीना गुप्ता की पहचान एक नेता के साथ साथ पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में रही है।

बड़े मुद्दों पर वह पार्टी की बात रखते हुए नजर आती हैं। भाजपा के विभिन्न आरोपों पर जबाद देते हुए उन्हें अक्सर इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी देखा जा सकता है। अभिनंदिता माथुर भी आप के लिए बड़ी भूमिका निभा रही हैं। आप के संगठन से लेकर सरकार के संस्कृति विस्तार कार्यक्रमों में उनकी बड़ी भूमिका रहती है। बहरहाल अब देखना यह है कि पार्टी नेतृत्व किस का नाम इस पद के लिए आगे बढ़ाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जिनका कहीं नाम नहीं था, उन्हें पद दिया गया है। दिल्ली की महापौर शैली ओबेबराय का उदाहरण सामने है।

MCD चुनाव के बाद रिक्त पद भी नहीं भरे

वैसे जानकारों की मानें तो दिल्ली महिला आयोग में अभी तक वे पद भी नहीं भरे जा सके हैं, जो दो सदस्यों के निगम चुनाव जीत जाने से रिक्त हुए थे। इसमें एक नाम प्रोमिला गुप्ता का है। उन्होंने निगम की तिमारपुर सीट से जीत हासिल की थी। दूसरा नाम सारिका चौधरी का है, इन्होंने भी महिला आयोग से इस्तीफा देकर नगर निगम की दरियागंज सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद से करीब एक साल से सदस्यों के दो पद रिक्त हैं।

क्या दूध के साथ आयरन की गोली लेना सेहत के लिए खतरनाक? यह भ्रम या सच्चाई, डॉक्टर से जान लें हकीकत

Iron Tablet And Milk Gap: डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और अन्य लोगों को आयरन की कमी पूरा करने के लिए आयरन की गोलियां लेने की सलाह देते हैं. अधिकतर लोग आयरन की गोलियां लेते समय कई जरूरी बातों का ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फायदा नहीं होता है. आज डॉक्टर से जानेंगे कि आयरन की गोलियां किस तरह खानी चाहिए.

आयरन हमारे शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व होता है और इसकी कमी होने से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. आयरन की कमी होने पर डॉक्टर लोगों को इसकी गोलियां देते हैं, ताकि जल्द से जल्द शरीर में इसकी कमी को पूरा किया जा सके. आमतौर पर गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और कुछ मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे लोगों को भी आयरन की गोलियां खाने की सलाह दी जाती है. हालांकि कुछ लोग आयरन की गोलियों को दूध के साथ लेने लगते हैं. अब सवाल है कि क्या आयरन की गोलियों को दूध के साथ लेना नुकसानदायक होता है? आखिर इन गोलियों को कब और किस तरह खाना चाहिए? चलिए इस बारे में डॉक्टर से हकीकत जान लेते हैं.

नई दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के प्रीवेंटिव हेल्थ एंड वेलनेस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉ. सोनिया रावत के मुताबिक दूध के साथ आयरन की गोलियों को नहीं खाना चाहिए. ऐसा करने से शरीर में उनका अब्जॉर्प्शन नहीं होता है और गोलियां खाने का कोई फायदा नहीं होता है. आयरन की टेबलेट को चाय या कॉफी के साथ भी नहीं लेना चाहिए. ऐसा करने से लोगों को किसी तरह का फायदा नहीं होगा. दूध के साथ आयरन की गोली लेने का कोई गंभीर खतरा तो नहीं है, लेकिन इससे दवा बेअसर हो जाती है और शरीर को कोई फायदा नहीं मिलता है.खासतौर से प्रेग्नेंट महिलाओं को इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए, वरना गर्भ में पल रहे बच्चे को पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं मिल पाएगा. इससे गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे बच्चे का स्वास्थ्य प्रभावित होगा.

सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है घुटनों का दर्द? जानें वजह

सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है घुटनों का दर्द? जानें वजहआगे देखें...

कैसे लेनी चाहिए आयरन की गोलियां?

डॉ. सोनिया रावत रहती हैं कि आयरन की गोलियों को हमेशा पानी या विटामिन सी से भरपूर जूस के साथ लेना चाहिए. आप ऑरेंज जूस के साथ आयरन की टैबलेट्स लेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा होगा. इसके अलावा आयरन की टेबलेट लेने के 2 घंटे बाद ही दूध पीना चाहिए. आयरन की गोली और खाने में भी 2 घंटे का गैप रखना चाहिए. अगर आपने खाना खा लिया है तो कम से कम 2 घंटे बाद आयरन की दवा लें. इस दवा की डोज और दवा लेने का समय आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं. खुद से दवा की डोज में कोई बदलाव न करें.

केले के साथ आयरन टेबलेट लेना सेफ

डॉक्टर की मानें तो कई बार आयरन की दवा लेने के बाद प्रेग्नेंट महिलाओं को उल्टी की शिकायत होने लगती है. ऐसे में अगर आप इस दवा को केले के साथ लेंगे, तो इससे किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नजर नहीं आएंगे और उल्टी से भी काफी हद तक राहत मिल जाएगी. इसके अलावा एक और जरूरी बात यह है कि लोगों को आयरन और कैल्शियम की दवा एक साथ नहीं लेनी चाहिए और इनमें भी कुछ घंटे का अंतर रखना चाहिए. एक साथ ये दवाएं लेने से शरीर को नुकसान हो सकता है. ऐसे में सावधानी बरतें.

संजय सिंह को राज्यसभा भेजने पर भड़की भाजपा

कहा- भ्रष्टाचार को पालने का काम कर रहे केजरीवाल

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले में जेल में बंद संजय सिंह को दोबारा राज्यसभा भेजने का निर्णय किया है। संजय सिंह का नाम आते ही विवाद बढ़ गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह को दोबारा राज्यसभा भेजने का निर्णय कर अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिया है कि उनकी राजनीति केवल भ्रष्टाचार के दम पर ही आगे बढ़ रही है। इससे उनकी ईमानदारी वाली राजनीति के दावे की असलियत भी खुलकर सामने आ गई है। संजय सिंह शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में इस समय जेल में बंद हैं। इसी महीने दिल्ली की तीनों राज्यसभा सीटें रिक्त हो रही हैं, जिन पर 19 जनवरी को चुनाव कराया जायेगा।

संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के बेहद भरोसेमंद साथी बनकर उभरे थे। राज्यसभा में वे मजबूती के साथ पार्टी की आवाज उठा रहे थे। उन्हें उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। वे दूसरे राज्यों में भी पार्टी के चुनाव प्रचार में मजबूती से सक्रिय रहते थे। लेकिन फिलहाल वे शराब घोटाले में जेल में बंद हैं, जिससे उनकी राजनीति को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई थी। लेकिन आज उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजने का निर्णय कर केजरीवाल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने साथियों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। हालांकि, भाजपा इसको बड़ा मुद्दा अवश्य बनाएगी। ऐसे में केजरीवाल के इस निर्णय का क्या राजनीतिक असर हुआ, यह देखने वाली बात होगी।

संजय सिंह के साथ-साथ दिल्ली महिला आयोग की चैयरमैन स्वाति मालीवाल को पहली बार राज्यसभा भेजने का निर्णय किया गया है। इसे पार्टी में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है। केजरीवाल पर यह आरोप लग रहा था कि वे पार्टी या सरकार में महिलाओं को पर्याप्त भागीदारी नहीं दे रहे हैं। दिल्ली में लंबे समय तक तक कोई महिला मंत्री नहीं थी। लेकिन बदले समीकरणों में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना को न केवल आगे बढ़ाया, बल्कि अब वे केजरीवाल के बाद सबसे मजबूत नेता बनकर उभरी हैं। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम में भी शैली ओबेरॉय को आगे बढ़कर केजरीवाल ने पार्टी के अंदर महिलाओं की भूमिका मजबूत करने की कोशिश की है। दिल्ली की तीसरी राज्यसभा सीट के लिए आम आदमी पार्टी ने एनडी गुप्ता को दोबारा अवसर देने पर सहमति जताई है।

पोल खुलने की डर से भेजा राज्यसभा

दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि संजय सिंह को दोबारा राज्य सभा के लिए नामांकित कर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने यह दिखा दिया है कि भ्रष्टाचार और अपराध को पालने में विश्वास करते हैं। इससे यह भी साबित होता है कि वे संजय सिंह के भ्रष्टाचार में बराबर के भागीदार हैं। केजरीवाल को यह डर है कि यदि संजय सिंह को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा, तो वो उनकी पोलखोल सकते हैं। यही कारण है कि केजरीवाल ने संजय सिंह को फिर से राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को राज्यसभा भेजने का निर्णय कर अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी में दो महिला नेताओं के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष को शांत करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि जब से दिल्ली सरकार में आतिशी मारलेना का कद बढ़ रहा था, तब से दोनों महिलाओं के बीच आपसी लड़ाई सतह पर आ गई थी। स्वाति मालीवाल सड़कों पर महिलाओं के लिए स्ट्रीट लाइट जैसे मुद्दे उठा कर आतिशी को लगातार असहज कर रही थीं। यही कारण है कि केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को राज्यसभा भेजकर पार्टी की आपसी लड़ाई को कम करने का प्रयास किया है।

> संजय सिंह के साथ-साथ दिल्ली महिला आयोग की चैयरमैन स्वाति मालीवाल को पहली बार राज्यसभा भेजने का निर्णय किया गया है। इसे पार्टी में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है। केजरीवाल पर यह आरोप लग रहा था कि वे पार्टी या सरकार में महिलाओं को पर्याप्त भागीदारी नहीं दे रहे हैं।

आने-जाने में हो रही थी दिक्कत, झंडेवाला मंदिर का गेट प्रबंधन ने खुद गिराया; एलजी ने की सराहना

उपराज्यपाल ने शुक्रवार देर शाम एक्स पर पोस्ट डाली कि रानी झांसी मार्ग पर स्थित प्राचीन झंडेवाला मंदिर ने मेरे अनुरोध पर स्वेच्छा से फुटओवर ब्रिज के बगल में बना अपना गेट गिरा दिया। यह अनुकरणीय पहल पैदल यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा। साथ ही उत्तर और दक्षिण दिल्ली को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क पर ट्रैफिक जाम को कम करेगा।

नईदिल्ली। जनहित में स्वतः अतिक्रमण हटाने के लिए एलजी वीके सक्सेना ने झंडेवाला मंदिर प्रबंधन की सराहना की है। उन्होंने शुक्रवार देर शाम एक्स पर पोस्ट डाली कि रानी झांसी मार्ग पर स्थित प्राचीन झंडेवाला मंदिर ने मेरे अनुरोध पर स्वेच्छा से फुटओवर ब्रिज के बगल में बना अपना गेट गिरा दिया।

यह अनुकरणीय पहल पैदल यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा। साथ ही उत्तर और दक्षिण दिल्ली को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क पर ट्रैफिक जाम को कम करेगा। उन्होंने आगे लिखा कि इससे ईदगाह, सदर बाजार, आजाद मार्केट, माडल बस्ती, पुल बंगश और मोतिया खान जैसे भारी भीड़भाड़ वाले इलाकों के निवासियों और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मंदिर प्रबंधन की नागरिक भावना को मेरा सलाम।

संजय सिंह फिर से जाएंगे राज्यसभा! जेल से नामांकन दाखिल करने पर कोर्ट ने दिया ये फैसला

संजय सिंह के अलावा दिल्ली से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता और नारायण दास गुप्ता का छह साल का कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है। नामांकन प्रक्रिया 2 जनवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी और 9 जनवरी पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। इस बीच संजय सिंह को जेल से नामांकन दाखिल करने की अनुमति मिल गई है।

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह इस बार जेल से ही राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन फार्म भरेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह के आवेदन पर सुनवाई के बाद उन्हें नामांकन जेल से नामांकन फार्म भरने की अनुमति दे दी है।

27 जनवरी को खत्म हो रहा संजय सिंह का कार्यकाल

27 जनवरी को संजय सिंह की सदस्यता समाप्त हो रही है। आप सांसद ने अनुमति के लिए दो आवेदन दाखिल किए थे। पहले आवेदन में संजय सिंह ने राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी नो ड्यूज प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर करने और दूसरे आवेदन में नामांकन पत्र भरने और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की अनुमति मांगी थी।

जेल से नामांकन दाखिल करने की मिली अनुमति

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आवेदनों का विरोध न किए जाने पर विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने दोनों आवेदनों को अनुमति दे दी। कोर्ट ने साथ ही जेल प्रशासन को नांमांकन फार्म समेत अन्य सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। खास बात है कि संजय सिंह के अलावा दिल्ली से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता और नारायण दास गुप्ता का छह साल का कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है। सभी सांसद आम आदमी पार्टी के हैं।

9 जनवरी है नामांकन की आखिरी तारीख

नामांकन प्रक्रिया 2 जनवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी और 9 जनवरी पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और वोटों की गिनती शाम 5 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को राज्यसभा में तीन सीटें आवंटित की गई हैं।

केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच डील डन! इस फार्मूले पर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव; सीट शेयरिंग भी तय

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ गुरुवार शाम हुई पार्टी की गठबंधन समिति की बैठक के दौरान सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे के रोडमैप पर चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का...

नई दिल्ली। 2024 के लोकसभा चुनाव चुनाव के लिए सारी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी जहां लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है तो वहीं, आईएनडीआईए के बैनर तले विपक्षी दल एकजुट होने में लगे हैं। साथ ही सीट बंटवारे को लेकर विपक्ष दलों में जोरशोर से मंथन चल रहा है।

सीट बंटवारे के रोडमैप पर हुई चर्चा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ गुरुवार शाम हुई पार्टी की गठबंधन समिति की बैठक के दौरान सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे के रोडमैप पर चर्चा हुई। बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे।

दिल्ली में अपना हाथ ऊपर रखा चाहती कांग्रेस

जानकारी के मुताबिक, लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में आप के साथ संभावित गठबंधन में कांग्रेस अपने अपना हाथ ऊपर रखना चाहती है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, आईएनडीआईए के सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे का जो फार्मूला तय हुआ है, उसके अनुसार, 2019 में जहां जिस सीट पर जो दल पहले या दूसरे नंबर पर रहा था, वह सीट उसी को दी जाएगी।

दिल्ली में कांग्रेस-AAP के बीच कौन-सा फार्मूला?

इस हिसाब में दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच पांच और दो सीट का फार्मूला बैठता है। ध्यान देने वाली बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सात में से पांच सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि दो सीटों पर आम आदमी पार्टी ने दूसरा स्थान पाया था। वहीं भाजपा ने दिल्ली की सातों लोकसभा सीट पर दर्ज की थी।

दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, दिल्ली के लिए अलग फार्मूला नहीं बनेगा, बल्कि यही रहेगा। अगर इस फार्मूले पर आम आदमी पार्टी के साथ बात नहीं बनीं तो संभावना है कि पांच- दो नहीं, तो चार- तीन का फार्मूला रखा जा सकता है। मतलब, चार सीट कांग्रेस को एवं तीन आप को दी जा सकती है।

अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ जांच करना और पूछताछ करना न्याय के हित में है।

दिल्ली में एक और भ्रष्टाचार केस की सीबीआई करेगी जांच, 223 करोड़ के घपले के मामले में एलजी ने दी मंजूरी

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के वन एवं वन्यजीव विभाग के दो अधिकारियों के खिलाफ 223 करोड़ रुपये भ्रष्टाचार मामले की सीबीआई जांच की अनुमति दे दी है। बुधवार को इस संबंध में अधिकारियों ने जानकारी दी है इसके साथ ही उपराज्यपाल ने रिश्वत के मामले में सरकारी अस्पतालों की दो नर्सों के खिलाफ एसीबी को जांच करने की अनुमति दे दी।

नईदिल्ली। दोनों मामलों में उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम की धारा 17ए के तहत जांच के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ जांच करना और पूछताछ करना न्याय के हित में है।

बता दें कि सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा की पहाड़गंज शाखा के पूर्व वरिष्ठ शाखा प्रबंधक एलए खान के साथ आपराधिक साजिश में शामिल होने के आरोप में वन और वन्यजीव विभाग में क्रमशः तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी पारसनाथ यादव और आलम सिंह रावत के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जाली पत्र के आधार पर अवैध रूप से ट्रांसफर किए पैसे

वे कथित तौर पर एक जाली पत्र के आधार पर संड्री खाते से उसी शाखा में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के नाम पर एक नकली बचत खाते में 223 करोड़ रुपये अवैध रूप से ट्रांसफर करने में शामिल थे। जाली पत्र वन और वन्यजीव विभाग द्वारा जारी किया गया था।

इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की दो महिला कर्मचारियों के खिलाफ कथित रिश्वत मामले में एसीबी ने उन पर दो नर्सिंग अधिकारियों से हल्की ड्यूटी की अनुमति देने के लिए प्रत्येक से 60,000 रुपये की मांग करने का आरोप लगाया। आरोपियों की पहचान चंचल रानी पिसल्ला और रजनेश वर्मा के रूप में हुई है, जो उस समय जीबी पंत अस्पताल में क्रमशः डिप्टी नर्सिंग अधीक्षक और नर्सिंग अधिकारी के रूप में तैनात थीं।

सीबीआई करेगी दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाओं की आपूर्ति मामले की जांच, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाओं की आपूर्ति की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का आदेश दिया है। बात दें दिसंबर में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना ने गृह मंत्रालय से मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस मामले पर दिल्ली सरकार का कहना था कि उसने पहले ही एलजी ऑफिस को इस बारे में जानकारी दे दी थी।

***नयी दिल्ली।** केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाओं की आपूर्ति की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का आदेश दिया है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बात दें, दिसंबर में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना ने गृह मंत्रालय से मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस मामले पर दिल्ली सरकार का कहना था कि उसने पहले ही एलजी ऑफिस को इस बारे में जानकारी दे दी थी।*

सतर्कता विभाग ने सौंपी थी रिपोर्ट

बता दें, सतर्कता विभाग ने नकली दवाओं को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपनी रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा गया था कि दिल्ली के कई अस्पतालों में नकली दवाओं की आपूर्ति की जा रही है। इसके बाद एलजी ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा था कि एलजी को इस संबंध में दो महीने पहले ही बता दिया था।

दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी, दो दिन छाया रहेगा घना कोहरा; नौ और 10 जनवरी को बारिश की उम्मीद

दिल्ली में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन यहां कोल्ड डे की स्थिति रही। दिन भर ठिठुरन एवं गलन का एहसास बना रहा। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार के लिए भी येलो अलर्ट कर दिया है। वहीं कड़ाके की ठंड के बीच अगले दो दिन मध्यम से घना कोहरा भी परेशान करेगा। अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री और न्यूनतम आठ से नौ डिग्री रहने की संभावना है।

नई दिल्ली। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन यहां कोल्ड डे की स्थिति रही। दिन भर ठिठुरन एवं गलन का एहसास बना रहा। सर्दी से बचने के लिए लोग कहीं अलाव तो कहीं हीटर जलाकर हाथ तापते हुए देखे गए।

शनिवार और रविवार के लिए येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार के लिए भी येलो अलर्ट कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, बृहस्पतिवार को दिल्ली के अधिकतम तापमान में सामान्य से सात डिग्री की कमी दर्ज की गई थी, जिससे गंभीर कोल्ड डे स्थिति बनी थी। शुक्रवार को हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी से बदलकर पूर्वी व उत्तर-पूर्वी रहा।

हवा की दिशा बदलने से तापमान में आंशिक वृद्धि हुई। इसीलिए समग्र रूप से राजधानी में कोल्ड डे की स्थिति रही, गंभीर कोल्ड डे की नहीं। दिन में आसमान साफ रहा, लेकिन धूप आज भी नहीं खिली। शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री कम 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

9.4 डिग्री सेल्सियस रहा न्यूनतम तापमान

वहीं न्यूनतम तापमान तीन डिग्री अधिक 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर 93 से 86 प्रतिशत रहा। सबसे कम अधिकतम तापमान 13.1 डिग्री के लिहाज से जाफरपुर और सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.1 की दृष्टि से रिज क्षेत्र दिल्ली के सर्वाधिक ठंडे इलाके रहे।

ब्याज के 400 रुपये और बदले की आग... गाजियाबाद में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खुला राज

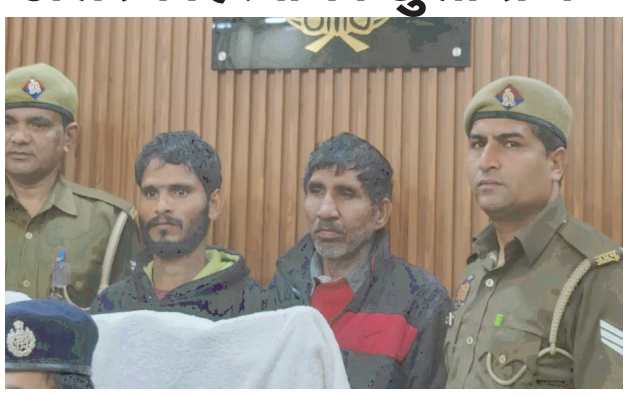

पूछताछ में पता चला कि ब्याज के शेष चार सौ रुपये मांगने पर उसने बाद में देने के लिए कहा तो सभी के सामने दुकान पर थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ का बदला लेने के लिए उसने हत्या की योजना बनाई। मदन के साथ मिलकर दूसरे दिन सुबह उसके घर पहुंचा। मदन कमरे के बाहर खड़ा निगरानी करने लगा। उसने चाकू से दिनेश की पीठ पर तेजी से एक वार किया।

साहिबाबाद। खोड़ा थाना क्षेत्र के नेहरु गार्डन में प्रॉपर्टी डीलर दिनेश मिश्र ने ब्याज के चार सौ रुपये नहीं देने पर भूरे उर्फ शहीद कुरैशी को थप्पड़ जड़ दिया था। थप्पड़ का बदला लेने के लिए उसने प्रॉपर्टी डीलर की साथी के साथ मिलकर हत्या कर दी।

हत्या का पुलिस ने किया पर्दाफाश

पुलिस ने दोनों आरोपितों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर घटना का राजफाश किया है। पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल ने बताया कि पकड़ा गया आरोप मोहल्ला हयातनगर खोड़ा का भूरा उर्फ शहीद कुरैशी और उसका साथी वंदना एन्क्लेव का मदन लाल हैं।

मुर्गे काटने वाले वाला चाकू बरामद

पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मुर्गे काटने वाला चाकू भी बरामद कर लिया है। पुलिस पूछताछ में भूरे ने बताया कि दिनेश से पांच माह पूर्व दो हजार रुपये उधार लिए थे। जो उसने चुका दिए थे। वह ब्याज के छह सौ रुपये और मांग रहा था। दो सौ रुपये दे दिए थे। दो जनवरी को दिनेश उनके यहां आया। ब्याज के शेष चार सौ रुपये मांगने लगा।

पीठ पर तेजी से किया वार

उसने बाद में देने के लिए कहा तो सभी के सामने दुकान पर थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ का बदला लेने के लिए उसने हत्या की योजना बनाई। मदन के साथ मिलकर दूसरे दिन सुबह उसके घर पहुंचा। मदन कमरे के बाहर खड़ा निगरानी करने लगा। उसने चाकू से दिनेश की पीठ पर तेजी से एक वार किया। वह लहूलुहान होकर चारपाई पर गिर गया। दोनों कमरा बाहर से बंद करके भाग गए।

फरियाद लेकर महिला से लेखपाल ने कहा- पहले खुश करो, फिर काम होगा; गुस्साई पीड़िता ने सिखाए ऐसे सबक...

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद में वसीयत केस में आदेश की कॉपी देने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने गुरुवार दोपहर मोदीनगर तहसील में लेखपाल की धुनाई कर दी। उन्हें कई चाटे जड़े। गाली-गलौज करते हुए उनपर जातिसूचक टिप्पणी की। सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की गई। आरोप है कि लेखपाल ने महिला से रिश्वत देकर खुश करने की बात कही थी।

गाजियाबाद। वसीयत केस में आदेश की कॉपी देने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने बृहस्पतिवार दोपहर मोदीनगर तहसील में लेखपाल की धुनाई कर दी। उन्हें कई चाटे जड़े। गाली-गलौज करते हुए उनपर जातिसूचक टिप्पणी की। सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की गई।

महिला ने लेखपाल पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। लेखपाल ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। दोनों की तरफ से मोदीनगर थाने में शिकायत दी गई। पुलिस ने लेखपाल की शिकायत पर महिला के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पति के साथ लेखपाल कार्यालय पहुंची महिला

गाजियाबाद जिले के मसूरी थाना क्षेत्र स्थित इंदरगढ़ी के सुधीर कुमार राजस्व विभाग में लेखपाल हैं। इन दिनों वे मोदीनगर तहसील के रजिस्ट्रार कानूनगो (आरके) कार्यालय में तैनात हैं। तिबड़ा गांव की एक महिला का तहसीलदार की कोर्ट में वसीयत का केस चल रहा था, जिसपर 19 दिसंबर को आदेश जारी हुए। वे बुधवार को आदेश की कॉपी लेने के लिए तहसील पहुंची तो लेखपाल ने टालमटोल कर उन्हें बृहस्पतिवार को आने को कहा। उसी के अनुसार वे बृहस्पतिवार दोपहर अपने पति के साथ रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय में पहुंची और सुधीर से आदेश की कॉपी मांगी।

लेखपाल ने महिला से कहा- पहले खुश करो

आरोप है कि इस एवज में लेखपाल महिला से रिश्वत मांगने लगा। कहा पहले खुश करना होगा। उनके साथ छेड़खानी भी की गई। महिला ने तुरंत लेखपाल को ताबड़तोड़ चाटे जड़ दिये। उनसे गाली-गलौज करते हुए जातिसूचक टिप्पणी की। पास खड़े अन्य कर्मचारियों ने महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। लेखपाल से अभद्रता करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

महिला का आरोप पूरी तरह से गलत है। ना तो रिश्वत मांगी गई और ना ही छेड़खानी की गई। मैं कार्यालय में काम कर रहा था। इसी बीच महिला ने आकर मारपीट शुरू कर दी। - सुधीर कुमार, लेखपाल

महिला ने सरकारी कर्मचारी के साथ तहसील में अभद्रता की है। सरकारी काम में बांधा भी डाली गई है। उसके खिलाफ थाने में शिकायत दी गई है। लेखपाल की भी भूमिका की जांच की जाएगी। - संतोष कुमार राय, एसडीएम मोदीनगर।

लेखपाल की शिकायत पर महिला के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। यदि महिला की भूमिका सामने आती है तो उसकी गिरफ्तारी होगी। - ज्ञान प्रकाश राय, एसीपी मोदीनगर

मोदीनगर में 30 वर्षीय युवक की चाकू घोंपकर हत्या, छत पर खून से लथपथ मिला शव

कोतवाली क्षेत्र के गांव बिसोखर में 30 वर्षीय युवक पवन की गला रेतकर हत्या कर दी गई। युवक का खून से लथपथ शव छत पर कमरे में मिला है। वारदात शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे की है। जानकारी के अनुसार थोड़ी देर पहले जब बच्चे छत पर कपड़े लेने पहुंचे तो शव देखकर शोर मचाने लगे। पवन ई रिक्शा चलाता था। वह तीन भाइयों में सबसे छोटा था। सू

मोदीनगर। कोतवाली क्षेत्र के गांव बिसोखर में 30 वर्षीय युवक पवन की गला रेतकर हत्या कर दी गई। युवक का खून से लथपथ शव छत पर कमरे में मिला है। वारदात शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे की है। जानकारी के अनुसार, थोड़ी देर पहले जब बच्चे छत पर कपड़े लेने पहुंचे तो शव देखकर शोर मचाने लगे। पवन ई रिक्शा चलाता था। वह तीन भाइयों में सबसे छोटा था। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके परपहुंच गई। फोरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाने में लगी है।

गाजियाबाद के इस इलाके में तीन दिन से सप्लाई बाधित, खारा पानी पीने को मजबूर लोग

परिवहन विशेष न्यूज

कोयल एन्क्लेव के-11 के ए बी व सी ब्लाक में 504 फ्लैट हैं। इनमें से करीब 75 फ्लैट में लोग रह रहे हैं। मंगलवार रात करीब 12 बजे पैनल में फाल्ट होने से तीनों ब्लाक की आपूर्ति बाधित हो गई थी। लोगों का आरोप है कि जीडीए में लगातार शिकायत करने के बाद भी आपूर्ति अभी तक सामान्य नहीं की गई है।

साहिबाबाद। कोयल एन्क्लेव के-11 सोसाइटी के पैनल में फाल्ट होने से पिछले तीन दिन से विद्युत आपूर्ति बाधित है। पावर बैकअप की सुविधा नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। शाम होते ही सोसाइटी में अंधेरा छा जाता है। आरओ नहीं चलने से लोग खारा पानी पीने को मजबूर हैं।

कोयल एन्क्लेव के-11 के ए, बी व सी ब्लाक में 504 फ्लैट हैं। इनमें से करीब 75 फ्लैट में लोग रह रहे हैं। मंगलवार रात करीब 12 बजे पैनल में फाल्ट होने से तीनों ब्लाक की आपूर्ति बाधित हो गई थी। लोगों का आरोप है कि जीडीए में लगातार शिकायत करने के बाद भी आपूर्ति अभी तक सामान्य नहीं की गई है।

शुक्रवार देर शाम तक केवल बी-ब्लाक में ही विद्युत आपूर्ति सामान्य हुई है। इससे करीब 15 परिवारों को राहत मिली है। बाकी ए व सी-ब्लाक के 60 परिवार अभी भी बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। सोसायटी के सुनील कुमार ने बताया कि शाम होते ही यहां अंधेरा छा जाता है। इससे लोगों को घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। बच्चे, बुजुर्ग व महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं।

अधिक टीडीएस का पीना पड़ रहा पानी

लोगों का कहना है कि यहां पर भू-जल की सप्लाई होती है। इस पानी का टीडीएस बहुत अधिक है। इसे कम करने के लिए घरों में आरओ लगाए गए हैं। लेकिन बिजली नहीं होने से आरओ बंद पड़े हुए हैं। इससे लोगों को अधिक टीडीएस का पानी ही पीना पड़ रहा है। कुछ लोग खरीदकर काम चला रहे हैं।

केवल सार्वजनिक क्षेत्र में है जेनरेटर सेट की सुविधा

सोसायटी के केवल कामन एरिया में जेनरेटर सेट से पावर आपूर्ति की सुविधा है। फ्लैट के लिए जेनरेटर की सुविधा नहीं है। सर्दी में बिजली नहीं होने से लोग पानी गर्म करने, हीटर चलाने समेत विभिन्न कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इससे यहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

पैनल में समस्या होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई थी। एक ब्लाक में आपूर्ति सामान्य हो गई है। बाकी दो ब्लाक में भी जल्द ही आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। विद्युत निगम मेंटेनेंस में सहयोग नहीं कर रहा है।

-विनोद कटारिया, सहायक अभियंता, जीडीए जोन-आठ

रात में खाना खाकर सोया परिवार सुबह उठा ही नहीं; पड़ोसी ने देखा तो उड़ गए होश

कानवनी में मजदूरी करने वाले मनीष बृहस्पतिवार देर रात को शीतलहर के चलते अंगीठी पर ताप रहे थे। नींद आने पर पूरा परिवार जलती अंगीठी छोड़कर सो गया। सुबह सीमा ने जाकर देखा तो पूरा परिवार बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। तुरंत एंबुलेंस बुलाकर घायल अवस्था में परिवार के चारों सदस्यों को संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया

गाजियाबाद। अंगीठी जलाकर सोने पर एक ही परिवार के चार लोगों की हालत बिगड़ गई है। कनावनी में मजदूरी करने वाले मनीष बृहस्पतिवार देर रात को शीतलहर के चलते अंगीठी पर ताप रहे थे। नींद आने पर पूरा परिवार जलती अंगीठी छोड़कर सो गया।

पूरा परिवार मिला बेहोश

सुबह सीमा ने जाकर देखा तो पूरा परिवार बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। तुरंत एंबुलेंस बुलाकर घायल अवस्था में परिवार के चारों सदस्यों को संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया। इमरजेंसी मेडिकल आफिसर डाक्टर योगेंद्र कुमार ने बताया कि 45 वर्षीय असमानी की हालत गंभीर है।

सांस लेने में भारी परेशानी

धुआं के चलते सांस लेने में भारी परेशानी होने लगी। आक्सीजन स्तर गिरने लगा। आक्सीजन देने के बाद भी सुधार नहीं हुआ तो बेहतर इलाज के लिए असमानी को जीटीबी दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा मनीष व उसके 11 वर्षीय बेटे कृष्ण और आट वर्षीय बेटी दीपाली की हालत नियंत्रण में है।

तीनों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। चिकित्सक की सलाह है कि शीत लहर से बचाव के लिए अलाव खुले स्थान में जलाना चाहिए। घर में जलाएं लेकिन सोने से पहले उसे जरूर बुझाना चाहिए। आग जलने से धुआं बरकरार रहता है। इससे सांस लेने में परेशानी होती है। दम घुटने से जान को खतरा रहता है।

चीनी मीडिया मोदी की तारीफ कर रहा है, चीनी राजनयिक आरएसएस मुख्यालय जा रहे हैं...यह चल क्या रहा है?

नीरज कुमार दुबे

जहां तक झांग जियादोंग के आलेख की बात है तो आपको बता दें कि इसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने हाल ही में दो बार भारत का दौरा किया। यात्राओं के दौरान मैंने पाया कि भारत की घरेलू और विदेशी स्थिति चार साल पहले की तुलना में काफी बदल गई है।

एक ओर भारत ने एक बार फिर कहा है कि चीन के साथ उसके संबंध ''सामान्य नहीं'' हैं तो दूसरी ओर दो बड़ी और हैरान करने वाली खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। दूसरी खबर यह है कि चीनी राजनयिकों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर मुख्यालय का दौरा करके आया है। सवाल उठता है कि क्या चीन की ओर से आरएसएस और भाजपा को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है? सवाल उठता है कि मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने अपने सख्त रुख के चलते जिस तरह सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर चीन को झटके पर झटके दिये हैं क्या उससे राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सारी हेकड़ी निकल गयी है?

हम आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स में भारत या भारत सरकार की तारीफ होना सामान्य बात नहीं है क्योंकि इस अखबार का काम भारत विरोधी एजेंडा चलाना और भारत के बारे में अफवाहें फैलाना है। इसलिए जब ग्लोबल टाइम्स में Zhang Jiadong ने अपनी हालिया भारत यात्रा का उल्लेख करते हुए भारत नैरेटिव की सराहना की तो सभी का चौंकना स्वाभाविक था। अगर लेखक अपने लेख में भारत या भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करने का साहस जुटा रहा है तो यकीनन इसके लिए उसने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनुमति ली होगी। इसलिए सवाल उठता है कि चीन के मन में कुछ और चल रहा है या उसे भारत की बढ़ती शक्ति का अहसास हो गया है?

जहां तक झांग जियादोंग के आलेख की बात है तो आपको बता दें कि इसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने हाल ही में दो बार भारत का दौरा किया। यात्राओं के दौरान मैंने पाया कि भारत की घरेलू और विदेशी स्थिति चार साल पहले की तुलना में काफी बदल गई है। भारत ने आर्थिक विकास और सामाजिक शासन में उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए हैं और इसकी महान शक्ति सपने से वास्तविकता की ओर बढ़ गई है। हालाँकि, संभावित जोखिम और संकट भी सामने आने लगे हैं।

वह लिखते हैं कि एक ओर भारत ने आर्थिक विकास और सामाजिक शासन में बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इसकी अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ ली है और यह सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर है। साथ ही नई दिल्ली ने शहरी प्रशासन में भी प्रगति की है। वह लिखते हैं कि हालाँकि धुंध अभी भी गंभीर है, लेकिन चार साल पहले विमान से उतरते ही जो विशिष्ट गंध आपको महसूस होती थी, वह आम तौर पर गायब हो गई है। इससे पता चलता है कि नई दिल्ली में सार्वजनिक माहौल कुछ बेहतर हुआ है।

वह लिखते हैं कि भारतीय प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान चीनी विद्वानों के प्रति उनका रवैया कहीं-कहीं अड़ियल होने की बजाय अधिक सहज और संयत रहा। उदाहरण के लिए, चीन और भारत के बीच ₹व्यापार असंतुलन₹ पर चर्चा करते समय, भारतीय विद्वान मुख्य रूप से व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए चीन के उपायों पर ध्यान केंद्रित करते थे। लेकिन अब वे भारत की निर्यात क्षमता पर अधिक जोर दे रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि इसके अलावा, अपने तीव्र आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ, भारत रणनीतिक रूप से अधिक आश्वस्त हो गया है और ₹भारत नैरेटिव₹ बनाने और विकसित करने में अधिक सक्रिय हो गया है।

वह लिखते हैं कि कूटनीतिक क्षेत्र में, भारत तेजी से एक महान शक्ति बनने की ओर बढ़ गया है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, उन्होंने अमेरिका, जापान, रूस और अन्य देशों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बहु-संरेखण रणनीति की वकालत की है। अब, विदेश नीति में भारत की रणनीतिक सोच में एक और बदलाव आया है और वह स्पष्ट रूप से एक महान शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने लिखा है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के संबंध में, भारत ने खुद को पश्चिम से दूर कर लिया है और खुद को विकासशील दुनिया के साथ अधिक निकटता से जोड़ लिया है। साथ ही, पश्चिमी शक्तियों के बारे में भारत की आपत्तियाँ काफ़ी कम हो गई हैं और पश्चिमी देशों के भीतर इसकी गतिविधियाँ लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि अब बड़े पैमाने पर प्रवासी कार्यक्रमों के आयोजन से भी ज्यादा आयोजन हो रहे हैं।

वह लिखते हैं कि राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में, भारत पश्चिम के साथ अपनी लोकतांत्रिक सहमति पर जोर देने से आगे बढ़कर लोकतांत्रिक राजनीति की ₹भारतीय विशेषता₹ को उजागर करने लगा है। वर्तमान में लोकतांत्रिक राजनीति के भारतीय मूल पर और भी अधिक जोर दिया जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने ₹लोकतंत्र के भारतीय संस्करण₹ की आवश्यकता पर बल दिया है।

वह लिखते हैं कि भारत न केवल औपनिवेशिक दासता की हर निशानी को मिटाना चाहता है बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से ₹विश्व संरक्षक₹ के रूप में भी कार्य करना चाहता है। उन्होंने लिखा है कि दिसंबर 2023 में, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने पहला ₹नॉलेज इंडिया विजिटर्स प्रोग्राम₹ आयोजित किया, जिसमें 35 देशों के 77 से अधिक विद्वान एक साथ आए। भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने एक मजबूत ₹भारत नैरेटिव₹ के निर्माण के महत्व पर जोर दिया और अर्थशास्त्र, विकास, राजनीति और संस्कृति के संदर्भ में ₹भारत नैरेटिव₹ की व्याख्या की। उन्होंने लिखा है कि जाहिर है, भारत अब सांस्कृतिक परंपरा के माध्यम से न केवल अपने हितों को साध रहा है बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहा है। वह लिखते हैं कि आंतरिक और बाह्य नीति में इस तरह के बदलाव भारत की दीर्घकालिक नीति के तर्क के अनुरूप हैं। भारत सदैव अपने आप को विश्व शक्ति मानता आया है। हालाँकि, भारत को बहु-संतुलन से बहु-संरेखण में स्थानांतरित हुए केवल 10 साल से भी कम समय हुआ है और अब यह बहुध्रुवीय दुनिया में एक ध्रुव बनने की रणनीति पर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में ऐसे बदलावों की गति कम ही देखने को मिलती है।

वह लिखते हैं कि भारत वास्तव में एक प्रमुख शक्ति है और आंतरिक और बाहरी रणनीतियों में तेजी से बदलाव उसके और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों के लिए चुनौतियाँ पैदा करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक परिवर्तित, मजबूत और अधिक मुखर भारत एक नया भू-राजनीतिक कारक बन गया है जिस पर कई देशों को विचार करने की आवश्यकता है।

चीनी राजनयिकों का आरएसएस मुख्यालय का दौरा

जहां तक चीनी राजनयिकों की ओर से संघ कार्यालय जाने की बात है तो आपको बता दें कि आरएसएस के पास पिछले महीने अप्रत्याशित मेहमान आए थे। देखा जाये तो चीन और आरएसएस वैचारिक रूप से एक दूसरे के विरोधी हैं। आरएसएस चीन की विस्तारवादी नीति का आलोचक है तो चीन भी संघ का विरोधी माना जाता है। इसलिए तब बड़ी हैरत हुई जब मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक चीन के राजनयिकों के एक समूह ने दिसंबर के पहले सप्ताह में नागपुर के रेशमबाग स्थित आरएसएस स्मृति मंदिर परिसर का दौरा किया। यह चीनी राजनयिकों की ओर से संघ मुख्यालय की पहली यात्रा थी। हम आपको यह भी बता दें कि वैसे हाल ही में विभिन्न देशों के राजनयिकों ने संघ मुख्यालय का दौरा किया है लेकिन चीनी राजनयिकों का दौरा बिल्कुल अप्रत्याशित था।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दिल्ली के साथ-साथ मुंबई स्थित देश के वाणिज्य दूतावास से चीनी राजनयिकों की एक टीम वर्धा में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का दौरा करने गयी थी। दरअसल हिंदी विश्वविद्यालय चीनी भाषा में भी पाठ्यक्रम चलाता है। वर्धा से चीन की टीम नागपुर भी आई और स्मृति मंदिर का दौरा किया। हालांकि चीनी प्रतिनिधिमंडल की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वह उस समय नागपुर से बाहर थे। बताया जा रहा है कि आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने चीनी राजनयिकों का स्वागत किया और उन्हें पूरे परिसर में घुमाया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आरएसएस के एक पदाधिकारी ने यात्रा की पुष्टि करते हुए कहा कि मेहमान शायद दूतावास या वाणिज्य दूतावास के मध्यम दर्जे के अधिकारी थे और उनके साथ विश्वविद्यालय का एक छात्र भी था। बहरहाल, हम आपको याद दिला दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 2020 के अपने विजयादशमी भाषण में गलवान झड़प का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने की जरूरत है और उद्देश्य हासिल करने के लिए अन्य पड़ोसियों के साथ भी अच्छे संबंध रखने की जरूरत है।

-नीरज कुमार दुबे

दिखने में लग्जरी और फीचर्स में शानदार ह्युंडई की ये शानदार कार, कीमत 10.96 लाख रुपये से शुरू

क्या आप भी अपने लिए एक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं जो दिखने में भी लग्जरी होआज हम आपको इस खबर के माध्यम से एक ऐसी ही कार के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है। मौजूद लग्जरी और शानदार कार Hyundai Verna है। इस कार में आपको दो इंजन का ऑप्शन मिलता है।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में एक से बढ़कर एक दमदार कारें मौजूद है। हर कोई अपने लिए जब एक नई कार लेने जाता है तो सबसे पहले यहीं सोचता है कि हमारी कार ऐसी हो जब वो रोड़ पर चले तो लोग देखते ही रह जाएं। क्या आप भी अपने लिए एक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं जो दिखने में भी लग्जरी हो और आपको बैठकर उसमें काफी प्रीमियम महसूस हो। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से एक ऐसी ही कार के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है।

Hyundai Verna इंजन

हम बात भारतीय बाजार में मौजूद लग्जरी और शानदार कार Hyundai Verna की कर रहे हैं। इस कार में आपको दो इंजन का ऑप्शन मिलता है। एक 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। जो 115 बीएचपी की पावर और 144 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन के साथ आती है। दूसरा इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। जो 160 बीएचपी की पावर और 253 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन केवल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। ये कार माइलेज 20 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर का देती है।

Hyundai Verna सेफ्टी फीचर्स

इस कार में सेफ्टी फीचर्स का भी खास ख्याल रखा गया है। 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक-फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), रिवर्स पार्किंग सेंसर, ऑटो हेडलैंप, आइसोफिक्स, टाइमर के साथ रियर डिफॉगर, इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, हाइट एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट मिलता है। इसके साथ ही इसमें हाई ट्रिम्स में हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट पार्किंग सेंसर, गाइडलाइन्स के साथ रियर पार्किंग कैमरा, टॉप वेरिएंट में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) भी मिलता है।

Hyundai Verna इंटीरियर

वहीं कार के इंटीरियर में 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के साथ एक डुअल स्क्रीन सेटअप भी मिलता है। इसमें आठ स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, सिंगल-पैन सनरूफ, एयर प्यूरिफायर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, इंफोटेनमेंट और एसी के लिए स्विचेबल कंट्रोल, 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है।

Hyundai Verna कीमत

भारतीय बाजार में मौजूद इस कार की कीमत ₹10.96 लाख रुपये है जो ₹17.38 लाख एक्स-शोरूम तक जाती है। ये कार कुल 14 वेरिएंट में आती है।

आने वाले दिनों में लॉन्च होंगी ये शानदार बाइक्स, एप्रीला से लेकर यामाहा तक शामिल

2023 in India आने वाले दिनों में कई दमदार बाइक्स भी लॉन्च होने वाली है। इटली की वाहन निर्माता कंपनी Aprilia दिसंबर के महीने में अपनी दमदार बाइक को लॉन्च कर सकती है। इस मोटरसाइकिल को वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में हुए Motogp के दौरान अनवील किया था। Kawasaki Eliminator 450 बाइक इस महीने के अंत में लॉन्च हो सकती है।

नई दिल्ली। Upcoming Bikes in December 2023 in India: भारतीय बाजार में टू-व्हीलर की डिमांड दिन पर दिन काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आने वाले दिनों में कई दमदार बाइक्स भी लॉन्च होने वाली है। अगर आप अपने लिए एक नई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम आने वाली है। चलिए आपको इन बाइक्स के बारे में बताते हैं।

Aprilia RS 457

इटली की वाहन निर्माता कंपनी Aprilia दिसंबर के महीने में अपनी दमदार बाइक को लॉन्च कर सकती है। इस मोटरसाइकिल को वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में हुए Motogp के दौरान अनवील किया था और अब ये इस महीने ही लॉन्च हो सकती है। इस बाइक में 457 सीसी का इंजन मिलता है। ये एक सुपर बाइक है। इसमें लिक्विड कूल्ड ट्विन सिलेंडर इंजन मिलेगा। जो 35 किलो वाट की पावर जनरेट करेगी।

Kawasaki Eliminator 450

ये बाइक इस महीने के अंत में लॉन्च हो सकती है। इस मोटरसाइकिल में 451 सीसी का इंजन मिलता है। वहीं इस बाइक को इस साल की शुरुआत में ही ग्लोबल स्तर पर लॉन्च किया गया था। अब ये भारत में भी लॉन्च हो सकती है। ये एक क्रूजर बाइक है। आपको बता दें, इसे कंपनी इंडिया बाइक वीक 2023 में लॉन्च कर सकती है।

Yamaha R3

Yamaha R3 एक दमदार और पॉपुलर बाइक में से एक है। इस बाइक को वाहन निर्माता कंपनी इसी साल लॉन्च कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बाइक 15 दिसंबर को लॉन्च हो सकती है। इसमें 321 सीसी का पावरफुल ट्विन मोटर इंजन मिलता है।

Yamaha MT-03

यामाहा अपनी इस सीरीज को भारत में लॉन्च करेगी। इस बाइक को साल के अंत में लॉन्च किया जा सकता है। इस मोटरसाइकिल की शुरुआती कीमत 3 लाख रुपये के आस-पास हो सकती है। इस बाइक के फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक मिलेगा। इसमें 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिल सकता है। इस बाइक का वजन 169 किलोग्राम होगा।

महिंद्रा स्कॉरपियो-N के डीजल वेरिएंट में ऐसा क्या कुछ खास की बढ़ी सेल, कीमत 13.26 लाख रुपये से शुरू

Mahindra Scorpio N total sale November 2023 Mahindra Scorpio-N के डीजल वेरिएंट के फीचर्स और इंजन के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर किन कारण से ये लोगों के बीच इतनी लोकप्रिय है। इस कार के माइलेज की बात करें तो इसके ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेट्रोल की माइलेज 10.14 किमी प्रति लीटर है जबकि डीजल वेरिएंट का माइलेज 12.73 किमी प्रति लीटर है।

नई दिल्ली। इंडियन मार्केट में महिंद्रा कई दमदार एसयूवी को लॉन्च कर चुकी है। मार्केट में इसकी सबसे लोकप्रिय एसयूवी में से एक Mahindra Scorpio-N है। इस कार की डिमांड काफी अधिक है। हालांकि लोगों के इसके पेट्रोल से अधिक डीजल वेरिएंट पसंद आ रहा है। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से Mahindra Scorpio-N के डीजल वेरिएंट के फीचर्स और इंजन के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर किन कारण से ये लोगों के बीच इतनी लोकप्रिय है।

Mahindra Scorpio-N

इस कार के माइलेज की बात करें तो इसके ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेट्रोल की माइलेज 10.14 किमी प्रति लीटर है, जबकि डीजल वेरिएंट का माइलेज 12.73 किमी प्रति लीटर है। वहीं माइलेज के अलावा इस कार के डीजल वेरिएंट से आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। पेट्रोल के मुकाबले डीजल वेरिएंट अधिक टॉर्क जनरेट करता है। इस कार की रीसेल वैल्यू भी काफी अच्छी है। ऑफ रोडिंग के लिए इसे अधिक पसंद किया जाता है। ये 4X4 ऑप्शन के साथ आती है।

Mahindra Scorpio-N कीमत

भारतीय बाजार में Mahindra Scorpio-N की एक्स शोरूम कीमत 13.26 लाख रुपये से 24.54 लाख रुपये के बीच है। इस एसयूवी में 6 और 7 सीटर का ऑप्शन मिलता है। इसमें 2.2 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है। जो 132 पीएस/300 एनएम और 175 पीएस (370 एनएम और 400 एनएम) से लैस है।

Mahindra Scorpio-N इंजन और पावर

इसके अलावा इस एसयूवी में 2 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है। जो 203 पीएस की पावर और 380 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 2WD (टू व्हील ड्राइव) 4WD (फोर व्हील ड्राइव) तकनीक के साथ 6-स्पीड मैनुअल/6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का भी ऑप्शन मिलता है।

Mahindra Scorpio-N फीचर्स

इस कार में फीचर्स के तौर पर 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, फ्रंट और रियर कैमरा, वायरलेस फोन चार्जिंग, 6 एयरबैग, एबीएस (एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम), टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) मिलता है।

पाकिस्तान में बलूचों का सत्याग्रह

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

पाकिस्तान में क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान है और सबसे ज्यादा अशांति व विद्रोह इसी बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान के इस विद्रोह को पाकिस्तान के खिलाफ राष्ट्रवादी विद्रोह के नाम से पुकारा जाता है।

बलूचियों की एक समस्या तो पाकिस्तान सरकार से है, लेकिन उनकी दूसरी समस्या चीन सरकार से है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की गिवादर बंदरगाह के बहाने लगभग उस इलाके का प्रशासन परोक्ष रूप से चीनी अधिकारियों के हवाले ही कर दिया है। चीनी अधिकारियों ने बलूचों को उनके अपने ही घर में दूसरे दर्जे का शहरी बना कर रख दिया है। जब कभी बलूचों और चीनियों में झगड़ा होता है, जो गाहे बगाहे होता ही रहता है, तो पाकिस्तान की सरकार चीनी अधिकारियों का साथ देती है, न कि बलूचों का। देखना होगा बलूच युवक-युवतियों का यह सत्याग्रह किस करवट बैठता है? फिलहाल अंतरिम प्रधानमंत्री भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, जो खुद बलूचिस्तान से संबंध रखते हैं'

पाकिस्तान में क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान है और सबसे ज्यादा अशांति व विद्रोह इसी बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान के इस विद्रोह को पाकिस्तान के खिलाफ राष्ट्रवादी विद्रोह के नाम से पुकारा जाता है। पाकिस्तान में रहने वाले एटीएम (अरब-तुर्क-मुगल मंगोल) का बलूचों पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि वे कट्टर मुसलमान नहीं हैं। उन्होंने सदियों पहले तुर्कों से पराजित हो जाने के बाद इस्लाम पंथ या शिया पंथ को स्वीकार तो कर लिया लेकिन अपनी पुरानी परम्परा, रीति रिवाजों और इतिहास को भी अपनाए रखा । या कम से कम उन्हें अपनी विरासत में से त्यागने से इन्कार कर दिया। पाकिस्तान के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे बलूची छात्रों को मोटे तौर पर इस्लाम विरोधी ही मान लिया जाता है। बलूचों की पाकिस्तान के खिलाफ यह लड़ाई पाकिस्तान के गठन से ही शुरू हो गई थी। दरअसल आज के बलूचिस्तान का बहुत सा हिस्सा 1947 से पहले कलात रियासत कहलाता था। अंग्रेजों के भारत छोड़ कर जाने से कुछ वर्ष पहले से ही यह सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद कलात रियासत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कलात रियासत को कैसे बचा कर रखा जा सकता है, इसके बारे में उसने उस समय के जाने माने वकील मोहम्मद अली जिन्ना से बात की। जिन्ना की दृष्टि में इसका एक ही तरीका था कि किसी तरह यह सिद्ध किया जाए कि कलात हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है। कलात के महाराजा ने इसको लेकर न्यायालय में मुकद्दमा दायर कर दिया और जिन्ना को ही अपना वकील बनाया। लेकिन जिन्ना मुकद्दमा जीत नहीं सके। तब तक पाकिस्तान बन गया। कलात के महाराजा का कहना था कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके तहत रियासतों को भारत या पाकिस्तान में रहना था, उस पर लागू

नहीं होता।

लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे नहीं माना। अब कलात के महाराजा के आगे बड़ा प्रश्न था कि वह भारत में रहे या पाकिस्तान में जाए? कलात के महाराजा ने यह अंदाजा लगा लिया था कि पाकिस्तान मोटे तौर पर इस्लामी राज्य बनेगा, जो बलूचों को रास नहीं आएगा। जिन्ना ने कलात के महाराजा को यह आश्वासन भी दिया कि यदि वह पाकिस्तान में शामिल हो जाता है तो उसकी सत्ता को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन उसने जिन्ना को नकार कर पंडित नेहरु को खत लिखा कि कलात रियासत भारत में शामिल होना चाहती है। लेकिन नेहरु ने उसकी इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। तब जिन्ना ने बलपूर्वक कलात को पाकिस्तान में मिला कर कलात नरेश को अपदस्थ कर दिया। और उसी दिन से बलोच सरदारों ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। पाकिस्तान सरकार ने उस विद्रोह को कुचला। लेकिन उसी दौर में बंगालियों ने पाकिस्तान के एटीएम को चुनौती देते हुए बंगला संस्कृति व भाषा की रक्षा के लिए लड़ते हुए पाकिस्तान से अलग होकर बंगला देश का निर्माण कर लिया। उससे बलूचों को नई ऊर्जा व प्रेरणा मिली। लेकिन अब तक बलूच सामाजिक संरचना में सरदारों का प्रभुत्व भी कम हो चुका था। तब दूसरे दौर की लड़ाई बलूचों की युवा पीढ़ी ने संभाली। इस नई पीढ़ी के लड़ाई में युवकों के साथ लड़कियां भी बहुत बड़ी संख्या में शामिल होने लगीं। पाकिस्तान ने इसका उत्तर अपने तरीके से दिया। जिस युवक या युवती पर थोड़ा सा भी संदेह हो जाता था कि वह बलूच समर्थक है और अभी भी बलोच संस्कृति या बलोच भाषा की बात करता है, उस पर बाकायदा नजर रखी जाती थी। इस अपशकुनि नजर के थोड़े दिनों बाद ही वह कालेज, विश्वविद्यालय या घर से गायब मिलता था। कुछ दिन बाद या तो उसकी लाश मिलती है या फिर वह सदा कि लिए गायब ही रहता है, यानी उसकी लाश भी नहीं मिलती। पाकिस्तान सरकार ने एक सीटीडी महकमा बना रखा है, जिसका शाब्दिक तर्जुमा तो 'आतंकवाद से लडने वाला विभाग' बनता है, लेकिन असल में इसका काम बलोच संस्कृति व भाषा के समर्थन में बात करने वाले युवक-युवतियों को गायब करना व उनको खत्म करना ही रह गया है। अब तक यह विभाग हजारों बलोचों को गायब कर चुका है।

पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह बात स्वीकार की है। जब घड़ा भरने लगता है तो प्रतिक्रिया तो होती ही है। पाकिस्तान के पश्तून इस मामले में अपने ढंग से प्रतिक्रिया कर रहे हैं। उनका टीटीपी यानी तहरीरे तालिबान पाकिस्तान बंदूक लेकर पाकिस्तान की सेना से लड़ रहा है। लेकिन बलोचों ने महात्मा गांधी का सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। 23 नवंबर 2023 को हजारों बलोच युवक-युवतियों का एक दल 1600 किलोमीटर की यात्रा तय करके पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की ओर चल पड़ा। सबसे बड़ी बात यह कि इसमें जितने युवक हैं, लगभग उतनी ही युवतियां शामिल हैं। इसका नेतृत्व भी तीस वर्षीय एक लडक़ी डा. महरंग बलूच ही कर रही थी। ध्यान में रहे, डा. महरंग के पिता भी चौदह साल पहले गायब हो गए थे। इस बार पिछले महीने टुरबट जिला के एक युवक बलाच बलोच को सीटीडी ने मार दिया था। उसी के कारण यह सत्याग्रह शुरू हुआ था। सत्याग्रही पाकिस्तान सरकार से इस गंभीर विषय पर बातचीत करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही इस सत्याग्रह का काफिला 1600 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके इस्लामाबाद पहुंचा तो सरकार ने उसका स्वागत उसी तरीके से किया जैसे कोई देश विरोधी देश के आक्रमणकारियों का करता है। बहुतों को पकड़ कर जेल में डाल दिया।

लाठीचार्ज से अंगभंग हो गए। सर्दियों का मौसम देखकर ठंडे पानी की बौछारों से सत्याग्रहियों को नहलाया गया। सत्याग्रहियों में बच्चे भी शामिल थे। शायद सत्याग्रहियों को आशा थी कि इस बार पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान के रहने वाले अनवर उल हक काकर को अंतरिम प्रधानमंत्री पद संभालने का अवसर दिया है, इसलिए काकर कम से कम अपने लोगों की बात तो सहानुभूति से सुनेंगे। लेकिन काकर का कहना है कि सत्याग्रह के लिए आने वाले बलोच घर जाकर आतंकवादियों में शामिल हो जाएं। सरकार को उनसे निपटना बखूबी आता है। बलूचियों की एक समस्या तो पाकिस्तान सरकार से है, लेकिन उनकी दूसरी समस्या चीन सरकार से है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की गिवादर बंदरगाह के बहाने लगभग उस इलाके का प्रशासन परोक्ष रूप से चीनी अधिकारियों के हवाले ही कर दिया है। चीनी अधिकारियों ने बलूचों को उनके अपने ही घर में दूसरे दर्जे का शहरी बना कर रख दिया है। जब कभी बलूचों और चीनियों में झगड़ा होता है, जो गाहे बगाहे होता ही रहता है, तो पाकिस्तान की सरकार चीनी अधिकारियों का साथ देती है, न कि बलूचों का। देखना होगा बलूच युवक-युवतियों का यह सत्याग्रह किस करवट बैठता है।

संपादक की कलम से

जांच के दायरे में दो मुख्यमंत्री

चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार-बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को ठुकरा रहे हैं, लिहाजा अंतिम परिणति जेल ही हो सकती है। केजरीवाल तीन बार और सोरेन 7 बार समन को खारिज कर चुके हैं। यह संविधान को अस्वीकार करना और उसका उल्लंघन करना ही है। केजरीवाल सरकार के दौरान 'शराब घोटाला' उछला और सोरेन 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में आरोपित हैं। सोरेन के खिलाफ चुनाव आयोग एक पत्र प्रदेश के राज्यपाल को भेज चुका है कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए और उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द की जाए। यह बंद चि_ी एक लंबे अंतराल से राज्यपाल के विचाराधीन है। न जाने विचार की प्रक्रिया कितनी लंबी होती है? दोनों मुख्यमंत्री विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के घटक हैं। उन्होंने संविधान की शपथ लेकर पद ग्रहण किया है और ईडी भी संवैधानिक जांच एजेंसी है। विपक्षी होने के मद्देनजर दोनों ही मुख्यमंत्री समन को 'राजनीतिक' करार दे रहे हैं और सरकारों को अस्थिर करने की साजिश भाजपा पर मढ़ रहे हैं। केजरीवाल तो कई बार कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे डरते हैं, लिहाजा चुनावों में निष्क्रिय करने के मद्देनजर ईडी जांच और जेल के जाल बिछाए जा रहे हैं। दोनों मुख्यमंत्री अपने-अपने घोटालों को लेकर खुद को मासूम मानते हैं, लिहाजा घोटालों के आरोपों का स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल के उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया बीते 11 माह से, शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों के कारण, जेल में हैं।

उनकी जमानत की दलील सर्वोच्च अदालत तक खारिज कर चुकी है। केजरीवाल की पार्टी के ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी घोटालों के आरोपों और साक्ष्यों के मद्देनजर जेल में कैद हैं। यदि इतने महत्त्वपूर्ण साथी जेल में हैं, तो क्या उन्होंने 'शराब नीति' का निर्णय खुद ही लिया था? कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता किसने की थी? जेल वाले साथियों ने शराब माफिया के कुछ चेहरों को, जो जेल में बंद हैं, मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर उनसे मिलवाया था, तो उसके प्रयोजन क्या थे? जिस मनी ट्रेरल की ओर सर्वोच्च अदालत ने भी संकेत किए हैं, क्या मुख्यमंत्री और 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर केजरीवाल उसमें संलिप्त नहीं थे? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पद का दुरुपयोग करते हुए खनन का पट्टा हासिल किया। बेशक बाद में उसे लौटा दिया हो, लेकिन ईडी ने मुख्यमंत्री के करीबियों के 12 ठिकानों पर छापे मारे हैं और संदिग्धों के मोबाइल तक जब्त किए हैं, 25 लाख और 8 लाख रुपए नकदी बरामद किए गए हैं, जिनका हिसाब संबद्ध व्यक्ति बता नहीं सके, तो यकीनन मामला गंभीर है। ईडी के समन नोटिसों को लगातार खारिज करके दोनों ही मुख्यमंत्री निर्दोष और मासूम साबित नहीं होंगे। उन पर सवाल और आरोप लटके रहेंगे। हमारे देश में सक्षम अदालतें भी हैं, जहां ईडी दस्तक देकर न्याय की गुहार कर सकता है। जांच एजेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 45 के तहत दोनों मुख्यमंत्रियों के लिए गैर जमानती वारंट जारी करने का भी अधिकार है, लिहाजा बार-बार समन की अवहेलना करने पर गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। क्या दोनों ही मुख्यमंत्री जेल जाने का संकट महसूस कर रहे हैं, लिहाजा समन की मंशा पर सवाल कर, उन्हें खारिज कर, ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं? दोनों को जांच का सामना करना चाहिए।

राय

दिल्ली समीक्षा से अपेक्षा

आगामी लोकसभा चुनाव की करवटों के बीच दिल्ली में कांग्रेस की मंत्रणा का सबूत बनकर हिमाचल से 33 नेताओं का जत्था, किस नए शपथपत्र पर हस्ताक्षर करेगा, यह देखना होगा। गिन कर केवल तीन राज्यों में अपनी सरकार चलाने वाली कांग्रेस के लिए चुनावी तस्वीर के कई पहलू हैं, जबकि इसके गणित में हिमाचल की गारंटियां भी गिनी जाएंगी। एक साल की सत्ता को लोकसभा जीत का परिणाम चाहिए तो सामने भाजपा की हर चाल से मुकाबला करने का संगठन और कार्यकर्ताओं का वजन चाहिए। दिल्ली गए तैंतीस नेता, अपने-अपने आश्वासन से कांग्रेस का सीना फुला सकते हैं, लेकिन इधर हिमाचल की पसलियों का दर्द न पार्टी और न ही सरकार ठीक से जानती है। यह नया दौर है जहां कांग्रेस को अपने नेतृत्व की कसौटी पर चार लोकसभा सीटों पर आधिपत्य स्थापित करना है। भाजपा से छीनी गई मंडी लोकसभा सीट पर वर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह की सियासी प्रतिभा का मुआयना होगा, तो कांगड़ा, हमीरपुर व शिमला में मुख्यमंत्री और सरकार के गठन को साबित करना है कि क्यों किसी संसदीय क्षेत्र से पांच, किसी से तीन और किसी से दो मंत्री चुने गए। इस तरह लोकसभा चुनाव की सबसे ताकतवर पिच शिमला होनी चाहिए जहां से आधा मंत्रिमंडल अपनी हैसियत का लोहा मनवा रहा है। हमीरपुर का ताज पहने स्वयं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा अभी-अभी शरीक किए गए बिलासपुर से राजेश धर्माणी का वर्चस्व देखा जाएगा। कांगड़ा अभी आहों के सफर पर पहले ही वरिष्ठ नेताओं को उदास कर चुका है, तो मंत्रिमंडल की रिक्तता में नेताओं की पद लालसा और महत्त्वाकांक्षा से चुनाव की महत्त्वाकांक्षा कितनी जुड़ती है, देखना होगा। दिल्ली की समीक्षा में अब तक असफल रहे सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा से यह अपेक्षा है कि ये दोनों नेता अपनी वरिष्ठता के आधार पर चुनावी नैया के पतवार थामें। संगठन और सरकार के सामने समन्वय के प्रश्न उठते रहे हैं, तो चुनावी मौसम में न जाने संतुलन के किस आधार पर कांग्रेस को मतदाता से अपना सियासी हक मांगना है। कम से कम भाजपा की तैयारियों, नेताओं की होशियारियों और संगठन की क्यारियों के जोश का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को अन्त्य परीक्षण व परीक्षा की जरूरत दिखाई देती है। कांग्रेस का जत्था दिल्ली से शुभ संकेत पाना चाहता है, इसलिए घर की बुनियाद पर बड़े नेताओं का पलस्तर खोजा जा रहा है, जबकि भाजपा अपनी दिल्ली की राह को प्रदेश में खोज रही है। भाजपा ने बतौर संगठन जो कुछ हिमाचल में बटोरा है, उसके विपरीत कांग्रेस का आशियाना खामोश है। भाजपा केंद्र सरकार के प्रदर्शन पर एक ओर मोदीत्व को आगे बढ़ा रही है, जबकि दूसरी ओर अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का महोत्सव बांट रही है। बहरहाल हिमाचल कांग्रेस का कुनबा दिल्ली दरबार में शरणागत है। देखना यह है कि पार्टी अपनी चिंताओं, भीतरी घावों, सरकार की चुनौतियों-गारंटियों तथा विक्षुब्ध नेताओं की खामोशियों को कैसे साधती है। चुनावी जीत की मंशा, मंतव्य और मंत्रणा के बीच पार्टी के लिए उम्मीदवारों को चिन्हित करने की कवायद के ऊंट किस करवट बैठते हैं, यह माथापच्ची का विषय है। दूसरी ओर विधानसभा चुनाव के उत्साह, समीकरण और संस्करण को लोकसभा के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जिंदा रखने की जरूरत है।

स्कूलों में फिटनेस कार्यक्रम कब?

भूपिंदर सिंह

तेज चलने, दौडने, शारीरिक क्रियाओं को करने से रक्त संचार तेज हो जाता है। मसल को उपयुक्त मात्रा में प्राणवायु मिलने से उसका समुचित विकास होता है। आज के विद्यार्थी को अगर कल का अच्छा नागरिक बनाना है तो स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाई के साथ फिटनेस कार्यक्रम भी देना होगा'

स्कूली स्तर पर फिटनेस कार्यक्रम शुरू करने की बात इस कॉलम के माध्यम से बार-बार उठाई जा रही है, मगर हिमाचल प्रदेश का कोई भी सरकारी या निजी स्कूल अपने यहां फिटनेस कार्यक्रम लागू करने में नाकाम रहा है। कई बार नए शिक्षा सत्र शुरू होकर खत्म हो गए, मगर फिटनेस कार्यक्रम कहीं भी शुरू नहीं हो पाया है। इस बार क्या सरकारी स्कूल अपने यहां या कोई निजी स्कूल पहल करेगा? शिक्षण विषयों के रिपोर्ट कार्ड की तरह स्वास्थ्य के मानकों का रिपोर्ट कार्ड भी प्रत्येक विद्यार्थी का हर स्कूल में अनिवार्य रूप से हो, क्योंकि भाषा व अन्य शिक्षण विषयों की तरह ही स्वास्थ्य के मूल स्तंभ स्पीड, स्ट्रेंथ, इडोरैंस व लचक आदि का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी उसी उम्र में शुरू करना होता है। शिक्षण विषयों के लिए तो स्कूलों के पास शिक्षक सहित पूरा प्रबंध है, मगर स्वास्थ्य के घटकों को विकसित करके उनका मूल्यांकन करने की कोई भी सुविधा आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस कॉलम के माध्यम से कई बार इस विषय पर स्कूलों व अभिभावकों को चेताया जा चुका है, मगर कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है।

किसी भी देश को इतनी क्षति युद्ध या महामारी से नहीं होती है जितनी तबाही नशे के कारण हो सकती है। आज जब देश के अन्य राज्यों सहित हिमाचल प्रदेश में भी नशा युवा वर्ग पर ही नहीं, किशोरों तक चरस, अफीम, स्मैक, नशीली दवाओं तथा दूरसंचार के माध्यमों के दुरुपयोग से शिकंजा कस रहा है, इसलिए सरकार, स्कूल प्रबंधन व अभिभावकों को इस विषय पर जरूरी कदम जल्दी ही उठा लेने चाहिएं। यदि विद्यार्थी किशोरावस्था में नशे से बच जाता है तो वह फिर युवावस्था आते-आते समझदार हो गया होता है। माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को विभिन्न विधाओं में व्यस्त रखने के साथ-साथ शारीरिक फिटनेस की तरफ मोडना बेहद जरूरी हो जाता है। मानव का सर्वांगीण विकास शिक्षा के बिना अधूरा है। शिक्षा की परिभाषा में साफ-साफ लिखा है कि यहां शारीरिक व मानसिक दोनों तरह से बराबर विद्यार्थियों का विकास करना है जिससे वह आगे चलकर जीवन को सफलतापूर्वक खुशहाल जी सके। शारीरिक विकास के लिए खेलों के माध्यम से फिटनेस कार्यक्रम बहुत जरूरी हो जाता है। खेल ही वह माध्यम है जिसके द्वारा विद्यार्थी को नशे से दूर रखा जा सकता है। पड़ोसी राज्य पंजाब एक समय तरक्की में देश का अग्रणी राज्य रहा है। खेलों में उत्कृष्टता उस प्रदेश की तरक्की व खुशहाली का भी पैमाना होती है। पंजाब में हजारों प्रशिक्षक विभिन्न खेलों में खेल प्रशिक्षण के लिए नियुक्त होने के साथ-साथ खेल प्रशिक्षण के लिए आधारभूत ढांचा होना वहां के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का प्रमुख कारण रहा था।

बाद में जब पंजाब धीरे-धीरे खेलों से दूर हुआ तो पहले वहां आतंकवाद और फिर आजकल पंजाब नशे का अड्डा बना हुआ है। यही कारण है कि हर क्षेत्र में आज हरियाणा पंजाब से काफी आगे निकल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एशियाई, राष्ट्रमंडल व ओलंपिक खेलों में पदक विजेता होने पर खिलाडियों को करोड़ों रुपए के नगद ईनाम व सम्मानजनक नौकरी देकर हरियाणा में खेलों के लिए बहुत ही उपयुक्त वातावरण तैयार किया है। उसी का नतीजा है कि आज हरियाणा का हर किशोर व युवा किसी न किसी खेल के मैदान में नजर आता है। हिमाचल प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश की खेलों के लिए अपने पहले कार्यकाल से ही कई महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश में कई खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्ले फील्ड, सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण तथा देश में प्रशिक्षक कैडर डाईंग हो जाने के बाद पहली बार प्रशिक्षकों की भर्ती जैसे बहुत बड़े खेल सुधार किए। हिमाचल प्रदेश की खेल सुविधाओं का प्रयोग राज्य में स्वास्थ्य व खेलों के लिए बड़े स्तर पर करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश इस समय शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। पिछले कुछ दशकों से हिमाचल प्रदेश के नागरिकों की फिटनेस में बहुत कमी आई है। इसका प्रमुख कारण है विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के लिए किसी भी प्रकार के फिटनेस कार्यक्रम का न होना। रट्टे वाली पढ़ाई की होड़ में हम विद्यार्थियों की फिटनेस को ही भूल गए हैं। हिमाचल प्रदेश की अधिकांश आबादी गांव में रहती थी। वहां पर सवेरे-शाम वर्षों पहले विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ कृषि व अन्य घरेलू कार्यों में सहायता करता था। विद्यालय आने-जाने के लिए कई किलोमीटर दिन में पैदल चलता था। इसलिए उस समय के विद्यार्थी को किसी भी प्रकार के फिटनेस कार्यक्रम की कोई जरूरत नहीं थी। आज का विद्यार्थी घर के आंगन में बस पर सवार होकर विद्यालय के प्रांगण में उतरता है। पढ़ाई के नाम पर ज्यादा समय खर्च करने के कारण फिटनेस के लिए कोई समय नहीं बचता है। अधिकांश स्कूलों के पास फिटनेस के लिए न तो आधारभूत ढांचा है और न ही कोई कार्यक्रम है।

आज का विद्यार्थी फिटनेस व मनोरंजन के नाम पर दूरसंचार माध्यमों का कमरे में बैठ कर खूब दुरुपयोग कर रहा है। ऐसे में विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की बात मजाक लगती है। आज के विद्यार्थी के लिए विद्यालय या घर पर आधे घंटे के फिटनेस कार्यक्रम की सख्त जरूरत है। इसमें 15 से 20 मिनट धीरे-धीरे दौडना तथा विभिन्न कोणों पर शरीर के जोड़ों की विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के बाद शरीर को कूलडाऊन करना होगा। कम से कम बीस मिनटों तक तेज चलने, दौडने व शारीरिक क्रियाओं को करने से रक्त वाहिकाओं में रक्त संचार तेज हो जाता है। उससे हर मसल को उपयुक्त मात्रा में प्राणवायु मिलने से उसका समुचित विकास होता है। आज के विद्यार्थी को अगर कल का अच्छा नागरिक बनाना है तो हमें स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाई के साथ-साथ ही उसके लिए सही फिटनेस कार्यक्रम भी देना होगा। तभी हम सही अर्थों में अपनी अगली पीढ़ी को संपूर्ण शिक्षित कर सकते हैं जो शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर अपने देश की सेवा कर सके।

हास्य रस

व्यंग्यकार की बेचैनी

जिस समय वे मेरे यहां आए, बेहद परेशान थे। अखबारों का बंडल हाथ में लिए शून्य में कहीं खोये थे। चाय पीने लगे तो मैंने ही कहा-'चाय में मजा नहीं आ रहा? मेरा मतलब मन ठीक तो है?' उन्होंने बिना पलक झपकाये हुये देखा और गहरी सांस लेकर चाय को सुडक़ा तथा फिर मौन साधक की भूमिका में आ गए। मैंने फिर उनकी तंद्रा को तोड़ा-'शायद आज कुछ नया नहीं लिख पाए हैं। व्यंग्यकार को विषयों की कमी नहीं है। आज की मुख्य खबर 'रेलें भिड़ीं' पर लिख मारिए व्यंग्य।' वे चौंके और अचकचाए-'हां, मैं भी इसी पर लिखना चाहता हूं। दूसरी खबरों में दम भी नहीं हैं, परंतु रेल भिडने पर क्या व्यंग्य हो सकता है?' मैं बोला-'रचना के ऊपर आप व्यंग्य लिखते हैं और वह व्यंग्य के कॉलम में छपती है, इसलिए वह रचना अपने-आप ही व्यंग्य हो गई। रचना में व्यंग्य आया या नहीं, इसकी परवाह आपने कब की है? आपको तो नित्यप्रति व्यंग्य लिखना है और उसे कहीं न कहीं छपवाना है, लिखकर भेज दीजिए, छप जाएगा।' 'शर्मा तुम कहना क्या चाहते हो?' उनके मुखारविंद से प्रश्न फूटा तो मैंने कहा-'कहना क्या है, व्यंग्य लिखने में आपका कोई दूसरा सानी नहीं है। दैनिक पत्रों की बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करते हो। रेलों के भिडने में व्यंग्य खोजिए। सदी की भीषण दुर्घटना है। इस पर लिखा हुआ जरूर छपेगा। मेरा आशय आपकी उन टिप्पणियों से है, जो व्यंग्य कहलाती हैं।' 'लेकिन यदि तुम मेरे लेखन से इतने प्रभावित हो तो यह बताओ, क्या नेपाल में भडक़ी हिंसा पर व्यंग्य नहीं हो सकता?' उन्होंने गम्भीर मुद्रा में कहा। मैं बोला-'आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? आपने तो ऐसी-ऐसी घटना-दुर्घटनाओं पर 'व्यंग्य' लिखे हैं, जिन पर व्यंग्य लिखने की व्यंग्यकारों ने कल्पना भी नहीं की है। व्यंग्य के लिए आप पुरस्कृत हुए हैं कई बार। मैं कैसे कह सकता हूं कि रेल और नेपाल में से कौनसा विषय ठीक रहेगा? जहां तक मेरा मानना है, अच्छा रहे आप दोनों पर व्यंग्य लिख दें। दोनों विषय ज्वलंत हैं और विसंगत मूल्य उनमें निहित हैं।'

'बात पते की कही है तुमने। विसंगति व्यंग्य को जन्म देती है। अब जरा यह बताओ कि इनमें विसंगति तुम्हारी नजर में क्या हो सकती है?' मैंने कहा-'इतना समझाया तो मैं खुद व्यंग्य नहीं लिख लेता। मैं भी आपकी ही तरह पत्र-पत्रिकाओं में छपता और नाम व दाम कमाता। विसंगति खोजना मेरे वश में नहीं है।' वे बोले-'मैं सामान्य आदमी के नजरिये से इन दोनों घटनाओं को देखना चाहता हूं।' दिमाग पर जोर देकर कुछ बोले-५मैं इन दोनों विषयों पर बहुत तीखा लिखना चाहता हूं।' 'वह तो आपकी परेशानी से लग रहा है कि आपका नित्यप्रति लिखना नितांत अनिवार्य है। चाहें तो आप सवाल खड़ा कर सकते हैं कि रेलें क्यों भिड़ी और नेपाल में हिंसा क्यों भडक़ी? आप तो शब्द शिल्पी हैं, दो-ढाई पृष्ठ लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। अखबारों की मांग पर दोनों व्यंग्य रचनाएं अब बहुत जरूरी हैं।' मैं बोला तो वे खड़े हो गए और मुड़े-तुड़े अखबारों को फैलाकर पढने लगे। मैंने कहा-'व्यंग्य में आधा विवरण तो घटना और दुर्घटना का देना है। आधा आपका एकालाप हो सकता है।' उन्होंने क्रोध से मुझे देखा और बोले-'तुम मुझे बता रहे हो कि व्यंग्य कैसे लिखा जाता है। तीन हजार व्यंग्य लिख चुका हूं मैं। मैं तो यों ही तुम्हारी राय जानना चाह रहा था, तुम तो देने लगे उपदेश।' 'नहीं..नहीं..नहीं..उपदेश मैं क्यों, आप दें, अपनी व्यंग्य रचना के माध्यम से। यह भी तो विसंगति और व्यंग्य है। मेरा मतलब आपका मासिक धर्म यह है कि तीस व्यंग्य रचनाएं आपकी छपनी चाहिए। उसके लिए विषय कोई भी हो सकता है। इधर वसंत आ रहा है, वसंत को भी क्यों छोड़ते हैं, उस पर भी लिखिए व्यंग्य।' इस बार वे ढीले पड़े और बोले-'तुम काम के आदमी हो। तुम्हारे पास कच्चा माल बहुत है। तुमसे नियमित मिला करूंगा।' मैं बोला-'मुझसे नियमित नहीं मिल पाओगे। इधर मेरे पास समयाभाव है और फिर मैं आप ही की तरह व्यंग्य लेखन की ओर उन्मुख होना चाहता हूं।' उन्होंने अखबार समेटे व मुझसे बिना बोले फटाफट चले गए। मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने मेरी उपेक्षा क्यों की? व्यंग्यकार की बेचैनी से मैं अनभिज्ञ था।

पूरन सरमा

इनसाइड

UPI ने दिया लोगों को नया अपडेट, इस दिन शुरू होगी यूपीआई की नई सर्विस, आपको मिलेगा यह लाभ

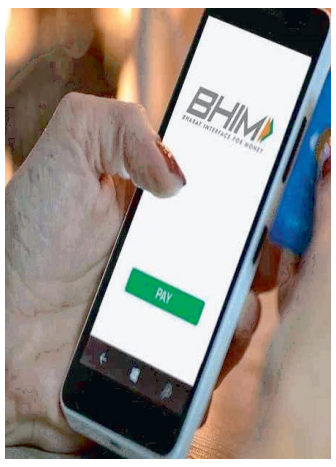

देश में ऑनलाइन पेमेंट की संख्या में तेजी देखने को मिली है। इस तेजी को बरकरार रखने के लिए RBI द्वारा कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। एमपीसी बैठक में UPI ट्रांजेक्शन की संख्या को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख का एलान किया। यह नया नियम 10 जनवरी से लागू होगा। केवल अस्पतालों और एजुकेशन सर्विसेस के लिए यूपीआई की लेनदेन की लिमिट को बढ़ाया गया।

नई दिल्ली। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) देश में यूपीआई की संख्या में तेजी लाने के लिए लोगों को नई सुविधा दी। दरअसल, 10 जनवरी 2024 से अस्पतालों और एजुकेशन सर्विसेस के लिए यूपीआई लेनदेन की लिमिट को बढ़ा दिया है। अब 5 लाख रुपये तक का ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले महीने निर्देश दिया था कि अस्पतालों और एजुकेशन सर्विसेस में अब 5 लाख रुपये तक की पेमेंट किया जा सकता है। पहले इन सेक्टर में यूपीआई पेमेंट को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। एनपीसीआई ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और यूपीआई एप्लिकेशन को लिमिट बढ़ाने का आदेश दिया है।

पहले यूपआई की लिमिट 1 लाख रुपये थी जो अब बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। यह लिमिट केवल वेरिफाइड मर्चेंट्स पर लागू होगा। ऐसे में मर्चेंट्स को पेमेंट मोड के रूप में यूपीआई को शुरू करना जरूरी है। वहीं यूपीआई के एक दिन की लिमिट 1 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

दिसंबर महीने में हुई मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी में आरबीआई ने यूपीआई लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इसका लाभ यूपीआई के सभी सहायक ऐप जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोनपे ऐप्स पर भी यह सुविधा मिलेगी। सभी बैंक में भी ग्राहकों को यह सुविधा दा जीएगी।

यूपीआई लेनदेन में तेजी

देश में यूपीआई पेमेंट में तेजी देखने को मिली है। वर्ष 2023 तक में यह 100 अरब के पार पहुंच गई। एनपसीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में लगभग 126 करोड़ यूपीआई पेमेंट हुई थी। वहीं, पिछले साल 2023 में इसकी संख्या में 60 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है।

आरबीआई ने केवाईसी के लिए राजनीतिक व्यक्तियों की परिभाषा को किया संशोधित

परिवहन विशेष न्यूज

आरबीआई ने अपने मानदंडों के तहत राजनीतिक रूप से संबद्ध व्यक्तियों (पीईपी) की परिभाषा को बदला है। इससे उन्हें कर्ज लेने समेत बैंक से जुड़े विभिन्न लेनदेन करने में सहूलियत होगी। इसके लिए आरबीआई ने (केवाईसी) नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। पीईपी से संबंधित पुराने मानदंड में स्पष्टता की कमी होने से बैंक अधिकारियों सांसदों और अन्य लोगों को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता था।

मुंबई। आरबीआई ने अपने मानदंडों के तहत राजनीतिक रूप से संबद्ध व्यक्तियों (पीईपी) की परिभाषा को बदला है। इससे उन्हें कर्ज लेने समेत बैंक से जुड़े विभिन्न लेनदेन करने में सहूलियत होगी। इसके लिए आरबीआई ने 'अपने ग्राहक को जानो' (केवाईसी) नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। पीईपी से संबंधित पुराने मानदंड में स्पष्टता की कमी होने से बैंक अधिकारियों, सांसदों और अन्य लोगों को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कई बार पीईपी के लिए कर्ज जुटाना या बैंक खाते खोलना मुश्किल हो रहा था।

आरबीआई ने केवाईसी मानक संशोधित किए

इस समस्या को देखते हुए आरबीआई ने राजनीतिक रूप से संबद्ध लोगों के लिए केवाईसी मानक संशोधित किए हैं। संशोधित केवाईसी निर्देशों के तहत पीईपी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी दूसरे देश ने प्रमुख सार्वजनिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें राज्यों/ सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के अधिकारी भी शामिल हैं।

नए नियमों में उस व्यक्ति को भी शामिल किया गया है जिसे किसी अन्य देश ने सार्वजनिक समारोह की जिम्मेदारी सौंपी है। पीईपी के बैंक खातों में मौजूदा प्रविधानों के तहत अतिरिक्त केवाईसी मानदंड हैं और एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी को इस बारे में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। केंद्रीय बैंक ने बैंकों और अन्य वित्तीय सेवाओं के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से इन बदलावों को तत्काल लागू करने के लिए कहा है।

सीपी और एनसीडी जारी करने के नियमों को किया गया सख्त

आरबीआई ने एक वर्ष तक की प्रारंभिक परिपक्वता वाले अल्पकालिक वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी करने के नियमों को सख्त कर दिया है। एक अप्रैल से लागू होने वाले नए मानदंडों में छह प्रमुख बदलाव शामिल हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ऐसे अल्पकालिक वाणिज्यिक पत्र की अवधि सात दिन से कम या एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है।

इसी तरह एनसीडी की अवधि 90 दिन से कम या एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। एक अप्रैल से जारी किए जाने वाले सीपी और एनसीडी का न्यूनतम मूल्य पांच लाख रुपये और उसके बाद पांच लाख रुपये के गुणक में होगा। इन दोनों ऋण उपकरणों (डेट इंस्ट्रूमेंट) को विकल्पों के साथ जारी नहीं किया जा सकता है।

इनका निपटान टी+4 कार्य दिवसों से अधिक की अवधि के भीतर किया जाना आवश्यक है। सीपी और एनसीडी केवल डीमैट रूप में जारी किए जाएंगे और सेबी में पंजीकृत डिपाजिटरी के पास ही रखे जा सकेंगे। एक खास बात यह है कि केंद्रीय बैंक ने इन उपकरणों के माध्यम से जुटाए गए धन की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है।

इन्कम टैक्स की इस सेक्शन से ले सकते हैं इन निवेश पर टैक्स कटौती का लाभ, जानिए कितना कम होगा आपका कर

देश के सभी टैक्सपेयर्स को समय पर टैक्स का भुगतान करना होता है। ऐसे में वह टैक्स कटौती का लाभ भी उठा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में कई सेक्शन का इस्तेमाल करके टैक्स कटौती का लाभ उठाया जा सकता है। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि टैक्स डिडक्शन का लाभ किस सेक्शन में कितना मिलता है।

नईदिल्ली। जब भी टैक्स सेविंग की बात आती होती है तो अक्सर लोगों को सेक्शन 80C और 80D के तहत टैक्स डिडक्शन के लिए अप्लाई करते हैं। आपको बता दें कि आप 80C के तहत 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स कटौती कर सकते हैं। वहीं, सेक्शन 80D के तहत आप मेडिकल के खर्चों पर टैक्ट कटौती का लाभ पा सकते हैं। इसके अलावा भी कई सेक्शन है जिसके जरिये आप आसानी से टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं

आइए, जानते हैं कि आप किस इन्वेस्टमेंट में टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं।

प्रोविडेंड फंड

कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी द्वारा जो भी निवेश किया जाता है वो टैक्स-फ्री होता है। इस टैक्स कटौती का लाभ केवल कर्मचारी को मिलता है। नियोक्ता को सेक्शन 80C के तहत कोई टैक्स कटौती का लाभ नहीं मिलता है। पीपीएफ में निवेश राशि के साथ ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। पीपीएफ योगदान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत यह कर कटौती के लिए पात्र है।

लाइफ इंश्योरेंस

लाइफ इंश्योरेंस में जो प्रीमियम का भुगतान होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। करदाता इस प्रीमियम पर धारी 80सी के तहट टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80डी के तहत मेडिकल प्रीमियम पर सालाना 25,000 रुपये तक के प्रीमियम पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। वहीं, हेल्थ चेकअप पर 5,000 रुपये तक के खर्च पर टैक्स कटौती का लाभ लिया जा सकता है।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश की गई राशि पर भी टैक्स डिडक्शन का लाभ उठाया जा सकता है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड में शामिल है। इसमें 1.50 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम किया जा सकता है। इस स्कीम में अर्जित इनकम और प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में शामिल किया जाता है। अगर यह 1 लाख रुपये से ज्यादा होती है तो उस पर 10 फीसदी तक का टैक्स का भुगतान किया जाता है।

दूसरे कारोबारी सत्र में भी जारी रही भारतीय करेंसी में तेजी, डॉलर के मुकाबले इतने उछला रुपया

Dollar Vs Rupee Rate आज वर्ष 2024 के पहला कारोबारी हफ्ता खत्म हो गया है। इस हफ्ते शेयर बाजार में उतरा-चढ़ाव के साथ भारतीय करेंसी में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वही आज शेयर बाजार भी हरे निशान पर बंद हुआ है।

नई दिल्ली। वर्ष 2023 के पहले कारोबारी हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार के साथ ही रुपया का शुरुआत नकारात्मक हुई थी, लेकिन बीच हफ्ते में इन दोनों में तेजी देखने को मिली थी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं, शेयर मार्केट भी उच्चतम स्तर पर बंद हुआ है।

फॉरेक्स ट्रेडर्स ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशों में मजबूत ग्रीनबैक ने स्थानीय इकाई के लाभ को सीमित कर दिया।

उच्चतम स्तर पर रुपया

आज अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में, स्थानीय इकाई ग्रीनबैक के मुकाबले 83.23 पर खुली। इसके बाज रुपया ग्रीनबैक के मुकाबले इंट्रा-डे में 83.24 के निचले स्तर और 83.12 के उच्चतम स्तर के बीच झूलता रहा और अंत में 83.16 पर बंद हुआ। यह पिछले बंद से 8 पैसे अधिक है।

डॉलर इंडेक्स हुआ मजबूत

दुनिया की बड़ी करेंसी के मुकाबले अमेरिकी मुद्रा की मजबूती बताने वाला डॉलर इंडेक्स 0.25 प्रतिशत गिरकर 101.68 पर बना हुआ है। कच्चे तेल में आज फिर तेजी देखी जा रही है और यह 0.90 प्रतिशत बढ़कर 78.29 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर है।

हरे निशान पर स्टॉक मार्केट

आज शेयर बाजार उच्चतम स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 178.58 अंक या 0.25 प्रतिशत बढ़कर 72,026.15 अंक पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 52.20 अंक यानी 0.24 प्रतिशत बढ़कर 21,710.80 अंक पर पहुंच गया। एक्सचेंज डेटा के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक ने गुरुवार को 1,513.41 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

सस्ता हुआ सोना तो चांदी में नहीं हुआ कोई बदलाव, आज आपके शहर में इतने रुपये में मिलेगा 10 ग्राम गोल्ड

वर्ष 2024 के कारोबारी हफ्ते में बीते दो दिन से सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। यह गिरावट वैश्विक कमजोर संकेतो की वजह से देखने को मिली। आज भी सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है तो वहीं चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चेक करें आपके शहर में कितना है सोने की कीमत?

नई दिल्ली। आज भी देश के छोटे-बड़े शहरों में सोने-चांदी के रेट अपडेट हो गए हैं। यह वैश्विक बाजार में सोने-चांदी की कीमतों के आधार पर तय किया जाता है। बीते दो कारोबारी सत्र से सोने और चांदी की कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है। आज भी सोने की कीमतों में गिरावट हुई है तो वहीं चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

अगर आप भी गोल्ड या सिल्वर की कोई ज्वेलरी खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको अपने शहर के लेटेस्ट रेट को जरूर चेक करना चाहिए।

कम हुई सोने की कीमत

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोने की कीमतें 100 रुपये गिरकर 63,450 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं। वरहीं बीते कारोबारी सत्र में 10 ग्राम गोल्ड 63,350 रुपये था। वैश्विक बाजारों में सोना 2,040 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर थे।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटी के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा

शुक्रवार को सोने में गिरावट जारी रही, विदेशी बाजारों में मंदी के रुझान के बाद दिल्ली के बाजारों में सोने की हाजिर कीमतें 100 रुपये की गिरावट के साथ 63,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही थीं। उम्मीद से बेहतर अमेरिकी मैक्रो डेटा और फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति ब्याज दर में कटौती की रणनीति पर अनिश्चितता के कारण डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी पैदावार बढ़ने से सोने की कीमतें दबाव में हैं

चांदी में नहीं हुआ कोई बदलाव

आज चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वैश्विक बाजारों में चांदी दोनों मामूली गिरावट के साथ 23.03 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर थे।

आपके शहर में क्या है 10 ग्राम सोने की कीमत

दिल्ली में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 63,400 रुपये है।

मुंबई में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 63,270 रुपये है।

कोलकाता में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 63,270 रुपये है।

चैन्नई में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 63,930 रुपये है।

बेंगलुरु में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 63,270 रुपये है।

हैदराबाद में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 63,270 रुपये है।

चंडीगढ़ में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 63,400 रुपये है।

जयपुर में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 63,400 रुपये है।

पटना में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 63,300 रुपये है।

लखनऊ में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 63,400 रुपये है।

यूपीआई से पेमेंट करने का है शौक तो भूलकर भी ना करें ये गलतियां, खाली हो जाएगा अकाउंट

अब हम 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की पेमेंट आसानी से यूपीआई के जरिये कर देते हैं। कई बार हम यूपीआई करते समय गलती कर दते हैं। यह गलती हमें काफी महंगी पड़ जाती है। देश में यूपीआई से जुड़े फ्रॉड की संख्या बढ़ गई है। आज हम इस आर्टिकल में जानते हैं कि यूपीआई करते समय हमें कौन-सी गलतियां करने से बचना चाहिए।

नई दिल्ली। आज के समय में किराने से लेकर कोई बड़ी पेमेंट के लिए हम यूपीआई करना काफी पसंद करते हैं। देश में यूपीआई की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। आप कुछ सेकेंड में PayTm, PhonePay, BHIM या बाकी यूपीआई ऐप के जरिये आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट की वजह से अब लोगों को कैश रखने की आवश्यकता नहीं होती है।

आपको बता दें कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करते समय काफी सावधानी रखने की जरूरत है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो यह आपको वित्तीय तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपको यूपीआई करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

यूपीआई पिन

आपको कभी भी अपना यूपीआई पिन किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। यूपीआई से पेमेंट करने से पहले हमसे पिन मांगा जाता है। अगर हम यह पिन किसी को साझा करते हैं तो कोई भी उस पिन का गलत इस्तेमाल करके अकाउंट से राशि निकाल सकते हैं। इस वजह से एक्सपर्ट भी सलाह देते हैं कि हमें यूपीआई पिन को पर्सनल रखना चाहिए।

इसके अलावा आप नियमित तौर पर अपनी यूपीआई पिन भी जरूर बदलें। यह आपके साथ होने वाले फ्रॉड की संभावना को काफी कम कर देता है।

स्क्रीन लॉक

आज लगभग सभी स्मार्टफोन में स्क्रीन लॉक की सुविधा मिल गई है। ऐसे में आपको खुद को किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए अपना स्क्रीन लॉक करना चाहिए। यह आपके सभी ऐप की सिक्योरिटी के साथ आपके पेमेंट को सिक्योर करता है। अगर आप अपने फोन का स्क्रीन लॉक नहीं करते हैं तो कोई भी बड़ी आसानी से आपके फोन को हैक कर सकते है।

अपने फोन और अपने यूपीआई ऐप को सिक्योर करने के लिए स्क्रीन लॉक करना काफी जरूरी है। यह आपके ऐप को सिक्योर करता है।

यूपीआई आई-डी वेरिफाई

आप जब भी कोई यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपको यूपीआई-आडी वेरिफाई करनी चाहिए। कभी भी पेमेंट करते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। अगर आप जल्दबाजी में पेमेंट करते हैं तो गलत यूपआई आईडी पर ट्रांजेक्शन की उम्मीद होती है। ऐसे में आप कभी गलत यूपीआई आईडी पर ट्रांजेक्शन ना करें इसके लिए आपको दोबारा यूपीआई आईडी की जांच करनी चाहिए।

एक से अधिक यूपीआई ऐप

कई लोग ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक स अधिक यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं। एक से अधिक यूपीआई ऐप से हमेशा बचना चाहिए। कई बार एक से अधिक यूपीआई ऐप की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे में कोशिश करें कि आप हमेशा से यूपीआई पेमेंट के लिए केवल एक ही ऐप का इस्तेमाल करें। आपको कभी भी किसी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए।

जल्द शेयर बाजार में Mobikwik की होगी लिस्टिंग, कंपनी ने SEBI में दोबारा फाइल किए ड्रॉफ्ट पेपर

बाजार में लिस्टिंग से पहले कंपनी को अपने आईपीओ का प्रस्ताव सेबी को देना होता है। आज मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड ने सेबी को ड्रॉफ्ट पेपर फाइल किया है। कंपनी इस आईपीओ के जरिये 700 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहे हैं। कंपनी ने 2021 में भी ड्रॉफ्ट पेपर फाइल किया था। मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड गुरुग्राम में स्थित है।

नई दिल्ली। मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड गुरुग्राम में स्थित है। यूनिकॉर्न फिनटेक फर्म वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड (MobiKwik Systems Ltd) ने आईपीओ के जरिये 700 रुपये जुटाने की योजना बना रहे हैं। इस राशि को जुटाने के लिए कंपनी ने सेबी के साथ ड्रॉफ्ट पेपर दाखिल किया है। कंपनी ने इससे पहले वर्ष 2021 में अपना ड्रॉफ्ट पेपर फाइल किया था। यह दूसरी बार है जब कंपनी ने ड्रॉफ्ट पेपर फाइल किया है।

पिछली बार कंपनी ने बाजार में प्रतिकूल स्थिति होने की वजह से आईपीओ की योजना को स्थगित कर दिया। कंपनी ने अपना ड्रॉफ्ट पेपर भी वापस ले लिया। कंपनी ने आज अपना ड्राफ्ट पेपर फाइल किया है। कंपनी इस आईपीओ में 700 करोड़ रुपये कलेक्ट करने की योजना बना रही है। कंपनी 700 करोड़ रुपये के फ्रेश इक्विटी जारी करेगी।

कंपनी 140 करोड़ रुपये तक की अपनी प्रतिभूतियों के प्री-आईपीओ प्लेसमेंट पर विचार कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कंपनी कम शेयर जारी कर सकती है। कंपनी आईपीओ से जुटाए राशि में से 250 करोड़ रुपये का इस्तेमाल वित्तीय सर्विस को बढ़ाने के लिए और 135 करोड़ रुपये अपने बिजनेस के लिए करेगी।

इसके अलावा, डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोडक्ट और प्रौद्योगिकी में निवेश के लिए 135 करोड़ रुपये और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए 70.28 करोड़ रुपये का इस्तेमाल करेगी।

मोबिक्विक के बारे में

मोबिक्विक कंपनी का प्रमुख एप्लिकेशन, उपभोक्ताओं को डिजिटल क्रेडिट, निवेश और बीमा में विभिन्न भुगतान ऑप्शन और फाइनेंस प्रोडक्ट तक पहुंच प्रदान करता है। इसकी स्थापना बिपिन प्रीत सिंह और उपासना टाकू ने की थी। 30 सितंबर, 2023 को समाप्त छह महीनों के लिए वन मोबिक्विक सिस्टम्स का परिचालन से राजस्व 381.09 करोड़ रुपये और टैक्स ऑफ्टर प्रॉफिट 9.48 करोड़ रुपये था।

एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड और डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं, और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आईपीओ के लिए रजिस्ट्रार है। कंपनी के इक्विटी शेयरों को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।

इस साल रिटायर होंगे 68 राज्यसभा सांसद

अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव सहित 60 भाजपा नेताओं का खत्म होगा कार्यकाल

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। पांच राज्यों में हुए चुनाव के बाद देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है। भाजपा और कांग्रेस समेत सभी बड़ी पार्टियां अपनी-अपनी जीत के लिए हर तरह का दांव खेलने को तैयार है।

लोकसभा चुनाव से पहले इस साल राज्यसभा से 68 सदस्य रिटायर होंगे, ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने-अपने नेताओं को सदन में फिट करने की जुगत में लग गई है।

रिक्तियों को लेकर लॉबिंग शुरू

इस साल राज्यसभा के 68 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे, इनमें नौ केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। राज्यसभा सदस्यों के सेवानिवृत्त होने के साथ राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच रिक्तियों को लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है। 68 रिक्तियों में से दिल्ली में आप नेता संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और सुशील कुमार गुप्ता 27 जनवरी को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। सिक्किम में एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए भी चुनाव होगा। एसडीएफ सदस्य हिशे लाचुंगपा 23 फरवरी को सेवानिवृत्त होंगे।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह सहित 57 नेता अप्रैल में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।

उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 10 सीटें रिक्त होंगी, इसके बाद महाराष्ट्र और बिहार (छह प्रत्येक), मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल (पांच प्रत्येक), कर्नाटक और गुजरात (चार प्रत्येक), ओडिशा, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश (तीन-तीन), झारखंड और राजस्थान (दो-दो), और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ (एक-एक) और चार मनोनीत सदस्य जुलाई में सेवानिवृत्त होंगे।

हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए दोबारा नामांकन के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपने गृह राज्य से बाहर सीट तलाशनी होगी क्योंकि वहां कांग्रेस सत्ता में है। कांग्रेस कर्नाटक और तेलंगाना से भी अपने उम्मीदवारों को संसद के उच्च सदन में भेजने की तैयारी कर रही है। कर्नाटक में चार और तेलंगाना में तीन राज्यसभा सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों में मनमोहन सिंह और भूपेन्द्र यादव (राजस्थान), अश्विनी वैष्णव, बीजद सदस्य प्रशांत नंदा और अमर पटनायक (ओडिशा), भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी (उत्तराखंड), मनसुख मांडविया और मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रूपाला, कांग्रेस सदस्य नारणभाई राठवा और गुजरात से अमी याग्निक शामिल हैं।

विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, एमएसएमई मंत्री नारायण राणे, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कांग्रेस सदस्य कुमार केतकर, एनसीपी सदस्य वंदना चव्हाण और शिवसेना (यूबीटी) सदस्य अनिल देसाई महाराष्ट्र से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। महाराष्ट्र में राकांपा और शिवसेना में विभाजन के कारण राज्य में राजनीतिक पुनर्गठन के बाद राज्यसभा चुनावों पर उत्सुकता से नजर रखी जाएगी। मध्य प्रदेश से धर्मेंद्र प्रधान, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन, भाजपा सदस्य अजय प्रताप सिंह और कैलाश सोनी और कांग्रेस सदस्य राजमणि पटेल संसद के उच्च सदन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कर्नाटक में सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों में भाजपा के राजीव चन्द्रशेखर और कांग्रेस के एल हनुमंथैया, जी सी चन्द्रशेखर और सैयद नासिर हुसैन हैं।

पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के सदस्य अबीर रंजन विश्वास, सुभाशीष चक्रवर्ती, मोहम्मद नदीमुल हक और शांतनु सेन और कांग्रेस सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी संसद के उच्च सदन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बिहार में राजद सदस्य मनोज कुमार झा और अहमद अशफाक करीम, जदयू सदस्य अनिल प्रसाद हेगड़े और बशिष्ठ नारायण सिंह, भाजपा सदस्य सुशील कुमार मोदी और कांग्रेस सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा में अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं।

भाजपा सदस्य अनिल अग्रवाल, अशोक बाजपेयी, अनिल जैन, कांता कर्दम, सकलदीप राजभर, जीवीएल नरसिम्हा राव, विजय पाल सिंह तोमर, सुधांशु त्रिवेदी और हरनाथ सिंह यादव और उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी सदस्य जया बच्चन सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश से टीडीपी सदस्य कनकमेदाला रवींद्र कुमार, भाजपा सदस्य सी एम रमेश और वाईएसआरसीपी सदस्य प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ से भाजपा सदस्य सरोज पांडे और हरियाणा से डी पी वत्स सेवानिवृत्त हो रहे हैं। झारखंड में भाजपा सदस्य समीर ओरांव और कांग्रेस सदस्य धीरज प्रसाद साहू मई में संसद के उच्च सदन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

हिट एंड रन: ट्रक चालक ऐसे दे सकेंगे दुर्घटनाओं की जानकारी, सड़क मंत्रालय ने एक तकनीकी प्रणाली का रखा प्रस्ताव

परिवहन विशेष न्यूज

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने सुझाव दिया है कि ट्रक चालकों को एक तकनीकी प्रणाली का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है। जिसके तहत वे अधिकारियों को दुर्घटना के बारे में सूचित कर सकते हैं ताकि ऐसे हादसे को नए कानून के तहत हिट-एंड-रन मामला न माना जाए।

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने सुझाव दिया है कि ट्रक चालकों को एक तकनीकी प्रणाली का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है। जिसके तहत वे अधिकारियों को दुर्घटना के बारे में सूचित कर सकते हैं ताकि ऐसे हादसे को नए कानून के तहत हिट-एंड-रन मामला न माना जाए।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने कहा, "यह मामला गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और वही आखिरी फैसला लेगा।"

उनका बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ ट्रक चालकों ने भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट-एंड-रन मामलों के लिए कड़े प्रावधानों के विरोध में हड़ताल की थी, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। इस हफ्ते की शुरुआत में, सरकार के साथ बातचीत के बाद हड़ताली ट्रक चालकों ने काम फिर से शुरू कर दिया था।

जैन के मुताबिक, ट्रक चालकों को लगता है कि अगर वे किसी व्यक्ति को टक्कर मारने के बाद उसकी मदद करने के लिए रुकते हैं, तो उन्हें जनता द्वारा नुकसान पहुंचाया जाएगा।

उन्होंने कहा, ₹तो, हम समाधान खोजने के लिए तकनीक का बुद्धिमानी से इस्तेमाल कर सकते हैं... हमने सुझाव दिया है कि चालक एक तकनीकी प्रणाली का उपयोग करके अधिकारियों को सूचित करे, और फिर इसे हिट-एंड-रन मामला नहीं माना जाएगा।

उन्होंने आगे कहा, ₹इसके बाद, चालक दुर्घटना स्थल से 25-50 किलोमीटर के दायरे में पुलिस को सूचित कर सकता है।₹

ट्रक चालकों के विरोध के बीच, अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस (एआईएमटीसी) के प्रतिनिधियों ने गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की।

2 जनवरी को, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हिट-एंड-रन मामलों से संबंधित नए दंडात्मक प्रावधान को लागू करने का निर्णय, जिसने ट्रक चालकों के विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है, सिर्फ एआईएमटीसी प्रतिनिधियों के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा।

कुछ ट्रक, बस और टैंकर ऑपरेटरों ने 'कठोर दंड' के प्रावधानों के विरोध में कई राज्यों में तीन दिवसीय हड़ताल की थी।

भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता के तहत, जो ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में शामिल होने के बाद अधिकारियों को सूचित किए बिना भाग जाएंगे, उन्हें 10 साल तक की कैद या 7 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता (IPC) में ऐसे मामलों के लिए दो साल की सजा का प्रावधान था।

वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान, एनएसओ ने जारी किए आंकड़े

वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान हैं।अनुमान जताया है इसकी बढ़ोतरी का कारण खनन और उत्खनन, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के कुछ क्षेत्रों का अच्छा प्रदर्शन हैं।

नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा शुक्रवार को अनुमानित आंकड़े जारी किए गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान हैं, जो पिछले वर्ष 7.2 प्रतिशत थी। अनुमान के मुताबिक, इसकी बढ़ोतरी का कारण खनन और उत्खनन, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के कुछ क्षेत्रों का अच्छा प्रदर्शन हैं।

NSO ने जारी की वित्त वर्ष के लिए अनुमानित आकंड़े

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा शुक्रवार को जारी अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 2022-23 में 1.3 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 6.5 होने का अनुमान हैं। वहीं, खनन क्षेत्र की वृद्धि चालू वित्त वर्ष में 8.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो 2022-23 में 4.1 प्रतिशत थी।

कई क्षेत्रों में दिखेगी वित्त वर्ष 2024 में तेजी

एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं में वित्त वर्ष 2023 में 7.1 प्रतिशत की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान हैं। एनएसओ बयान में कहा गया है कि वर्ष 2023-24 में 171.79 लाख करोड़ रुपये का स्तर प्राप्त करने का अनुमान हैं, जबकि वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी का अनंतिम अनुमान 160.06 लाख करोड़ रुपये हैं। वहीं 2023-24 के दौरान वास्तविक जीडीपी में वृद्धि 2022-23 में 7.2 फीसदी की तुलना में 7.3 फीसदी रहने का अनुमान है।

वर्तमान अनुमान के मुताबिक, अर्थव्यवस्था का आकार 2023-24 के दौरान 296.58 लाख करोड़ रुपये या 3.57 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान हैं। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण खंड से संबंधित सेवाओं की वृद्धि दर 2022-23 में 14 प्रतिशत से कम होकर 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। निर्माण क्षेत्र चालू वित्त वर्ष में सालाना आधार पर 10 फीसदी से बढ़कर 10.7 फीसदी की दर से बढ़ने की संभावना है। सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं की वृद्धि वित्त वर्ष 2013 में 7.2 प्रतिशत के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष में 7.7 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान हैं।

उत्तराखंड में चार शहरों से अयोध्या के लिए चलेंगी रोडवेज बसें, सीएम ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री धामी के आदेश के बाद परिवहन निगम टनकपुर के अलावा अब हरिद्वार, रामनगर व ऋषिकेश से अयोध्या रोडवेज बस सेवा की तैयारी में जुट गया है।

देहरादून। अब रोडवेज बस से भी अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में प्रमुख स्थलों से अयोध्या के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए। परिवहन निगम चार स्थानों से अयोध्या के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू करने की तैयारी में जुट गया है।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री धामी ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में सभी बस स्टेशनों को स्वच्छ और आधुनिक सुख-सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में क्रैश बैरियर और सड़कों के किनारे पौधरोपण किया जाए। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों की फिटनेस टेस्टिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। वाहन चालकों के प्रशिक्षण और मेडिकल की भी समुचित व्यवस्था की जाए।

कहा, यातायात नियमों के प्रति लोगों को निरंतर जागरूक किया जाए। रोडवेज की बसों के माध्यम से सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रचार भी किया जाए। जनसुरक्षा की दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्रों में पुराने वाहनों की जगह पर नए वाहनों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने महत्वपूर्ण स्थलों से अयोध्या के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए।

इसके तहत परिवहन निगम टनकपुर के अलावा अब हरिद्वार, रामनगर व ऋषिकेश से अयोध्या रोडवेज बस सेवा की तैयारी में जुट गया है। सीएम ने कहा, राज्य में श्रद्धालुओं, पर्यटकों की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए नए बस स्टेशन बन रहे हैं। यहां मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि वाहनों पर नंबर प्लेट स्पष्ट दिखें।

कहा, नंबर प्लेट से छेड़खानी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उधर, काठगोदाम से अयोध्या सेवा तीन जनवरी से शुरू हुई है, जो काठगोदाम से रात आठ बजे से और हल्द्वानी से रात 8:30 बजे से चलकर सुबह 5:30 बजे लखनऊ पहुंचेगी। वहां से सुबह नौ बजे अयोध्या पहुंच जाएगी। शाम को तीन बजे वापस चलेगी।

मोदी राज में भारत में 60 प्रतिशत बढ़ी राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, सड़क सचिव ने किया खुलासा

नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से, दिसंबर 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 60 प्रतिशत बढ़कर 1,46,145 किलोमीटर हो गई है, जो 2014 में 91,287 किलोमीटर थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

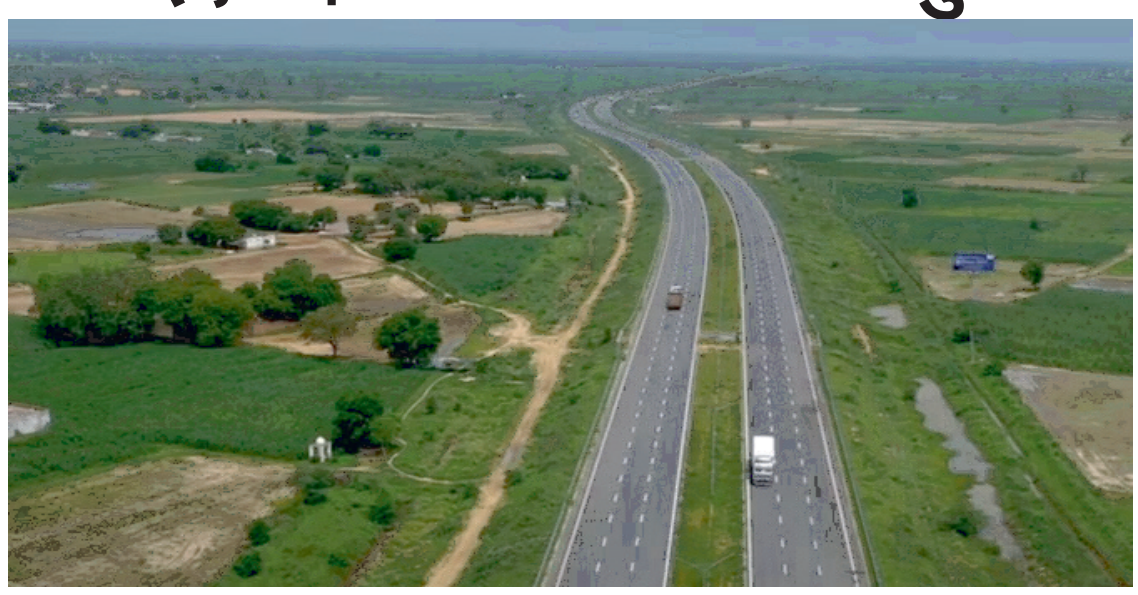

नई दिल्ली। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जैन ने कहा कि दिसंबर 2023 में चार लेन और उससे ऊपर के राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की कुल लंबाई 2014 के 18,387 किलोमीटर से 2.5 गुना बढ़कर 46,179 किलोमीटर हो गई है।

2014 में कुल हाई-स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 353 किलोमीटर थी, जो 2023 में बढ़कर 3,913 किलोमीटर हो गई। जबकि 2 लेन से कम वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2014 के 30 प्रतिशत से घटकर 2023 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 10 प्रतिशत रह गई। जैन ने यह भी कहा कि सड़क मंत्रालय ने दिसंबर 2023-24 तक राष्ट्रीय राजमार्गों के 6,217 किलोमीटर का निर्माण किया है।

उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रालय के राजमार्ग निर्माण पर खर्च 2014 से 2023 में 9.4 गुना बढ़कर 3.17 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

जैन ने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत, भारत में 44 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (RVSF) चालू हैं। जबकि रियायत और मोटर वाहन टैक्स की घोषणा 19 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई है।

उन्होंने यह भी बताया कि अब तक वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत 49,770 वाहनों को स्क्रैप किया जा चुका है।

जैन ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में दिसंबर तक सरकारी स्वामित एनएचएआई ने टोल के रूप में 18,450 करोड़ रुपये का संग्रह किया है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023